

करछना हिंसा के आरोपियों से मिलने जेल पहुंचे कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय, पुलिस से नोकझोंक

प्रयागराज। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय शनिवार को इलाहाबाद के सांसद उज्ज्वल रमण सिंह और बाराबंकी के सांसद तनु पुनिया के साथ नैनी जेल पहुंचे। उन्होंने करछना हिंसा के मामले में जेल में बंद आरोपियों से मुलाकात की। अजय राय को शिकायत मिली थी कि जेल प्रशासन जेल में बंद भडेवरा हिंसा के आरोपियों से किसी को मिलने नहीं दे रही है। भीम आर्मी के अध्यक्ष और सांसद चंद्रशेखर आजाद रावण को नजरबंद करने के बाद करछना में भड़की हिंसा और आगजनी



के मामले में जेल में बंद आरोपियों से मिलने के लिए कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय शनिवार को नैनी जेल पहुंचे। वाहनों के लंबे काफिले और बड़ी संख्या में कार्यकर्ताओं के साथ जेल पर पहुंचे अजय राय को जेल प्रशासन ने जेल से कुछ दूर पहले ही रोक लिया। अजय राय के साथ इलाहाबाद के सांसद उज्ज्वल रमण सिंह और बाराबंकी के सांसद तनु पुनिया भी थे। जेल के अंदर को लेकर जेल प्रशासन से नोकझोंक हुई। बाद में अजय राय और दोनों सांसदों को जेल में अंदर जाकर मुलाकात करने की अनुमति दी गई, जबकि अन्य नेताओं को बाहर ही रोक दिया गया। वरिष्ठ जेल अधीक्षक अमिता दुबे और जेल अधीक्षक एसपी सिंह तीन लोगों के अलावा अन्य किसी को जेल के भीतर जाने की अनुमति नहीं दी।

प्रेमी जोड़े ने एक दूसरे का हाथ पकड़कर नए यमुना पुल से लगाई छलांग, खोजबीन में जुटे गोताखोर

प्रयागराज। प्रेमी जोड़े ने शनिवार को नए यमुना पुल से छलांग लगा दी। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार सुबह करीब आठ बजे प्रेमी जोड़ा नए पुल पर पहुंचा। कुछ देर बातचीत की। इसके बाद एक दूसरे का हाथ पकड़कर उफनाई यमुना में छलांग लगा दी। पुलिस ओर गोताखोर खोजबीन में जुटे हैं। नए यमुना पुल से शनिवार सुबह एक प्रेमी युगल ने छलांग लगा दी। घटना की जानकारी होने पर जल पुलिस ने दोनों की खोजबीन शुरू कर दी है, लेकिन उनका कुछ पता नहीं चल सका। प्रत्यक्षदर्शियों ने पुलिस से बताया कि दोनों ने पहले पुल पर पहुंचकर कुछ देर बातचीत की। फिर एक दूसरे का हाथ थामकर यमुना में कूद गए। यह देखकर पुल से गुजर रहे राहगीरों की भीड़ जमा हो गई। शोरगुल होने पर पुलिस पहुंच गई। नदी में कूदने की आवाज सुनकर नीचे तैनात जल पुलिस ने बचाव कार्य शुरू कर दिया। पुलिस को पानी में उतराया एक बैग मिला, जिसमें कुछ कपड़े मिले हैं। आशंका जताई जा रही है कि बैग उन्हीं दोनों में से किसी एक का है। हालांकि अभी उनकी पहचान नहीं हो सकी है। कीडगंज पुलिस बैग और कपड़े के माध्यम से दोनों की पहचान कराने में जुटी है।

पी.आर.पब्लिक स्कूल में नेत्र परीक्षण शिविर का आयोजन

मुजफ्फरनगर के पचेंड़ा रोड स्थित पी.आर.पब्लिक में आज दिनांक 12/7/ 2025 को भारत विकास परिषद मुजफ्फरनगर ‘दिव्या’ शाखा की ओर से वरदान धर्मार्थ चिकित्सालय ,प्रेमपुरी, मुजफ्फरनगर के सहयोग से निशुल्क नेत्र जांच शिविर का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ प्रांतीय प्रकल्प प्रभारी राष्ट्रीय पर्व अशोक सिंघल(स्कूल प्रबंधक) प्रधानाचार्य अनघ सिंघल जी तथा भारत विकास परिषद नेत्र परीक्षण शिविर दिव्यााखा के उपस्थित सदस्यों श्री राजीव मित्तल, श्रीमती जिज्ञासा मित्तल(प्रकल्प प्रभारी) श्री कमल गोयल (अध्यक्ष) श्रीमती नैना गोयल (संयोजिका महिला सहभागिता) प्रवीण सिंघल (अध्यक्ष) किशोर कुमार जैन (कोषाध्यक्ष) श्री अनिल गोपाल गर्ग , श्री मनोज गुप्ता , श्री विचित्र विजय गुप्ता, प्रवीण कुमार ,आकाश जी आदि द्वारा मां सरस्वती के समक्ष दीप प्रज्वलित कर किया गया। स्कूल प्रबंधन समिति द्वारा उपस्थित सभी गण मान्य जनों का माला पहनाकर स्वागत किया गया। उपस्थित डॉक्टरों की टीम द्वारा कक्षा 6 से 8 तक के लगभग डेढ़ सौ छात्र— छात्राओं के नेत्रों की जांच की गई। जिनमें लगभग 50 छात्र— छात्राओं की आंखें कमजोर पाई गई। डॉक्टर की टीम के द्वारा बच्चों को अपनी आंखों की रोशनी को सही रखने के लिए उचित खान—पान तथा सारस—समय पर नेत्र परीक्षण करते रहने के निर्देश दिए गए । स्कूल शिक्षक —शिक्षिकों ने भी अपने नेत्रों की जांच कराई। इस अवसर पर स्कूल प्रधानाचार्य अनघ सिंघल ने नेत्र शिविर दिव्य शाखा के सभी सदस्यों के इस निस्वार्थ सेवा भाव की स राहना करते हुए कहा कि आंखें हमारे शरीर का अमूल्य अंग है। जो हमें जीवन के अद्भुत अनुभवों का भागीदार बनाने में सक्षम है इसलिए उनकी सेहत और सुरक्षा का ध्यान रखना हमारे लिए बहुत आवश्यक है। उचित खान—पान तथा सही देखभाल कर हम अपनी आंखों को जीवन पर्यंत स्वस्थ रख सकते हैं। स्कूल प्रबंधक अशोक सिंघल जी ने कार्यक्रम के समापन में अपने संबोधन में कहा कि उपस्थित सभी गणमान्यजनो का स्कूल प्रांगण में इस निशुल्क नेत्र परीक्षण शिविर लगाने के लिए आभार व्यक्त करते हुए कहा —हमें अपनी आंखों की रोशनी को स्वस्थ बनाए रखने के लिए अपने भोजन में विटामिन ए ,सी से भरपूर फल, सब्जियों को शामिल करना चाहिए तथा इसके साथ—साथ हमें टी वी, मोबाइल फोन आदि को लगातार लंबे समय तक नहीं देखना चाहिए। अधिक धूल और धुआ वाले स्थान में आंखों पर चश्मा लगाकर चलना चाहिए। अपनी आंखों के स्वास्थ्य को प्राथमिकता दें तथा जीवन भर स्पष्ट दृष्टि का लाभ उठाएं। आज के इस कार्यक्रम के सफलतापूर्वक संचालन में प्रवीण कुमार, दिव्या शर्मा, रजनी गोयल, शंकर शर्मा, अनुपम सैनी, मीनू वर्मा, शिखा ठाकुर आदि का विशेष योगदान रहा।

किरायेदार को कोई हक् नहीं कि वह जर्जर भवन गिराने का विरोध करे, जिंदगी की सुरक्षा सबसे बड़ी

प्रयागराज। याची का दावा है कि उसका भवन 100 साल पुराना है। जर्जर हालत में है। उसने इसके पुनर्निर्माण के लिए भवन के ध्वस्तीकरण की अर्जी नगर निगम अलीगढ़ में दिया था। अधिकारियों ने भवन को गिरने की अनुमति दे दी लेकिन भवन में रह रहे किरायेदारों के विरोध के कारण ध्वस्तीकरण की कार्रवाई नहीं हो पा रही। इस पर याची ने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया है।

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा कि किरायेदार को कोई हक नहीं कि वह जर्जर भवन गिराने का विरोध करे। जिंदगी की सुरक्षा किरायेदारी के अधिकारों से कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण है। यह टिप्पणी न्यायमूर्ति अश्वनी कुमार मिश्रा और न्यायमूर्ति जयंत बनर्जी की खंडपीठ ने अलीगढ़ निवासी अशोक कुमार गुप्ता की याचिका पर की है। कोर्ट ने नगर निगम अलीगढ़ को याची के जर्जर को गिराने की इजाजत दे दी।

याची का दावा है कि उसका

भवन 100 साल पुराना है। जर्जर हालत में है। उसने इसके पुनर्निर्माण के लिए भवन के ध्वस्तीकरण की अर्जी नगर निगम अलीगढ़ में दिया था। अधिकारियों ने भवन को गिरने



की अनुमति दे दी लेकिन भवन में रह रहे किरायेदारों के विरोध के कारण ध्वस्तीकरण की कार्रवाई नहीं हो पा रही। इस पर याची ने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया है।

याची के अधिवक्ता ने दलील दी कि मानसून के आने पर भवन के गिरने की आशंका है।

इससे जनहानि हो सकती है लेकिन किरायेदार इसका विरोध कर रहे हैं। लिहाजा, उन्हें भवन से बेदखल कर ध्वस्तीकरण की इजाजत दी जानी चाहिए। नगर निगम की ओर से भी यही दलील



शपथपत्र में दोहराई गई।

नगर आयुक्त ने जवाबी हलफनामा दाखिल कर कोर्ट को बताया कि आगामी मानसून के मौसम में भवन गिरने से जनहानि की आशंका है। लिहाजा, निगम नागरिकों के जीवन की सुरक्षा के लिए सभी आवश्यक कदम उठा रहा है।

सावन में बाबा बैजनाथ धाम की राह होगी आसान, हर सोमवार चलेगी स्पेशल ट्रेन

मंगलवार 15 जुलाई से 12 अगस्त तक होगा।

गोविंदपुरी से (गाड़ी संख्या 04158) सुबह 8रु15 बजे चलकर पूर्वाह्न 11रु40—11रु45 बजे प्रयागराज जंक्शन एवं

जंक्शन और सुबह 8रु40 बजे गोविंदपुरी पहुंच जाएगी। एनसीआर के सीपीआरओ शशिकांत त्रिपाठी ने बताया कि 20 कोच की इस ट्रेन में 18 जनरल कोच एवं दो एसएलआर



अगली सुबह 4रु01—4रु11 बजे जसीडीह और सुबह 6रु30 बजे आसनसोल पहुंच जाएगी।

इसी तरह आसनसोल से 04157 प्रत्येक मंगलवार सुबह 7रु45 बजे चलकर सुबह 9रु45—9रु55 बजे जसीडीह एवं अगले दिन तड़ के 3रु55—4रु00 बजे प्रयागराज

के कोच रहेंगे।

गंगा गोमती और लखनऊ इंटरसिटी एक्सप्रेस में बढ़ेगा एसी चेयरकार कोच संगम नगरी से प्रदेश की राजधानी लखनऊ जाने वाली गंगा गोमती एक्सप्रेस और लखनऊ इंटरसिटी एक्सप्रेस में यात्री सुविधा के मद्देनजर एसी

भारत का जिक्र किए बिना पाकिस्तान का समर्थन करना प्रथमदृष्टया देशद्रोह नहीं, जमानत अर्जी मंजूर

प्रयागराज। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा कि भारत या किसी घटना का जिक्र किए बिना पाकिस्तान का समर्थन करना प्रथमदृष्टया देशद्रोह का अपराध नहीं बनता है। भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता को खतरे में डालने वाले कार्य करने पर ही देशद्रोह की धाराओं में मुकदमा दर्ज किया जाना चाहिए।

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा कि भारत या किसी घटना का जिक्र किए बिना पाकिस्तान का समर्थन करना प्रथमदृष्टया देशद्रोह का अपराध नहीं बनता है। भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता को खतरे में डालने वाले कार्य करने पर ही

देशद्रोह की धाराओं में मुकदमा दर्ज किया जाना चाहिए। यह टिप्पणी करते हुए कोर्ट ने पाकिस्तान के समर्थन में पोस्ट करने वाले आरोपी को सशर्त जमानत दे दी। यह आदेश न्यायमूर्ति अरुण कुमार सिंह देशवाल की पीठ ने संभल के रियाज की जमानत अर्जी पर दिया।

संभल के बहजोई थाने में रियाज पर देशद्रोह की धारा में मुकदमा दर्ज किया गया है। आरोप है कि उसने इंस्टाग्राम पर प्वाहो जी हो जाए सपोर्ट तो बस..... को सपोर्ट किया गया था, जिसमें एक व्यक्ति की मौत हो गई थी और पांच लोग गंभीर रूप से घायल हुए थे। हाजी युनुस का आरोप है कि अनस ने ही अपने पिता हाजी अलीम की हत्या करवाई थी और मैंने उसपर मुकदमा दर्ज कराया है। साथी मुकदमे की पैरवी कर रहा हूं।

इसी रंजिश में जेल में रहते हुए षड्यंत्र कर उनके व उनके साथियों पर जानलेवा हमला कराया। अनस लंबे समय से जेल में बंद है और उसने हाईकोर्ट में जमानत के लिए याचिका दाखिल की थी। याची के अधिवक्ता अभिषेक कुमार सरोज व नगेंद्र बहादुर सिंह ने दलील दी कि यह उनकी चौथी जमानत अर्जी है और सह अभियुक्तों को पहले ही जमानत मिल चुकी है। शिकायतकर्ता ने सह अभियुक्तों की जमानत को चुनौती दी थी, लेकिन वह विफल रहे। राज्य सरकार के अधिवक्ता ने जमानत याचिका का विरोध किया, लेकिन अदालत ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद अनस को सशर्त जमानत दे दी।

कोर्ट ने याचिका स्वीकार करते हुए नगर निगम को याची के जर्जर भवन की गिराने की इजाजत दे दी। कोर्ट ने यह भी कहा कि ध्वस्तीकरण से पहले किरायेदारों को उनका सामान घर से हटाने का समुचित अवसर प्रदान किया जाए।

कोर्ट की टिप्पणी जर्जर भवन में रह रहे किरायेदारों के जीवन को खतरे से बचाना किरायेदारी अधिकारों की तुलना में अधिक जरूरी है। किरायेदारी अधिनियम की धारा 21(2) के तहत मकान मालिक मरम्मत, पुनर्निर्माण या ध्वस्तीकरण के लिए किरायेदारों की बेदखली के लिए आवेदन कर सकता है। वहीं उत्तर प्रदेश नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 331(1) यह अधिकार देती है कि अगर कोई संरचना किसी के लिए खतरा बन गई तो नगर आयुक्त उसे गिराने का आदेश दे सकते हैं।

चेयरकार का एक—एक कोच बढ़ाया जाएगा। दोनों ही ट्रेनों में वर्तमान में एसी चेयरकार का एक—एक कोच ही है। प्रयागराज संगम रेलवे स्टेशन से 14 कोच की गंगा गोमती ट्रेन की रवानगी सुबह 5रु40 बजे होती है, जो सुबह 9रु55 बजे लखनऊ पहुंचती है। इसी तरह लखनऊ से शाम 6रु15 बजे चलकर रात 10.25 बजे संगम स्टेशन पहुंच जाती है।

वहीं, 13 कोच की इंटरसिटी की रवानगी प्रयागराज संगम से दोपहर 3रु20 बजे चलकर शाम 7रु35 बजे लखनऊ एवं वापसी में लखनऊ से सुबह 7रु35 बजे रवाना होकर 11रु45 बजे ट्रेन प्रयागराज संगम पहुंचती है। लखनऊ मंडल के सीनियर डीसीएम कुलदीप तिवारी ने बताया, दोनों ही ट्रेनों में जल्द ही एसी चेयरकार का एक—एक और कोच जोड़ा जाएगा।

31 जुलाई तक हज आवेदन स्वीकार किए जाएंगे

प्रयागराज में छः हज ई—सुविधा केन्द्र बनाए गए

प्रयागराज। हज कमेटी ऑफ इण्डिया मुम्बई द्वारा हज 2026 की अधिकारिक घोषणा कर दी गई है। जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी द्वारा आरनेलास हॉयर सेकेंडरी स्कूल, (पालकी), नुरुल्लाह रोड को हज—ई सुविधा केंद्र बनाया गया है। कमेटी के सचिव हाजी मोईन अहमद ने दिल्ली में रहते हुए ऑनलाइन बैठक में शामिल रहते हुए बताया कि कार्यालय में प्रातरु 10 बजे



से एक बजे तक एवं शाम को 7 बजे से 9 बजे तक हज फॉर्म निरुशुल्क भरा जाएगा। उपसचिव एवं हज ट्रेनर हाजी शाह सऊद ने जायरीनों को जानकारी देते हुए बताया कि हज आवेदक जिनके पासपोर्ट की वैधता 31 दिसम्बर 2026 तक है, वह सभी आवेदक अपने साथ पासपोर्ट साइज व्हाइट बैकग्राउंड फोटो, पासपोर्ट, आधार कार्ड, चेक बुक या पासबुक साथ में लेकर कार्यालय आएँ। फॉर्म भरने के अंतिम तिथि 31जुलाई है। इस संदर्भ में एक बैठक आरनेलास हॉयर सेकेंडरी स्कूल, (पालकी) गेस्ट हाउस में हुई। बैठक में एडवोकेट अल्टमस नाजिम अंसारी, हाजी सादिक अली, हाजी आसिफ अनवार और हाजी मजहद अली आदि मौजूद रहे। इसके अलावा प्रयागराज में हज ई—सुविधा केन्द्र मदरसा मोहम्मदिया महेवा, मदरसा मदरसतुल बनात मोहिद्दीनपुर भरेठा, तहसील—सदर, मदरसा अनवारुल उलूम (ब्यायज) हटिया, बहादुरगंज, मदरसा खदीजतुल कुबरा लिलबनात, हंडिया और रज़ाए मुस्तफा खिदमते हुज्जाज सोसाईटी, शगुन पैलेस को भी बनाया गया है।

राष्ट्रपति को संबोधित ज्ञापन दिया गया

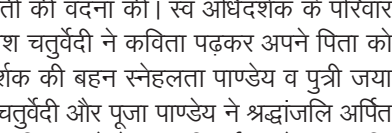
बिजनौर। लोक जनशक्ति पार्टी (रामविलास) ने बिजनौर में राष्ट्रपति को संबोधित एक ज्ञापन जिला अधिकारी को सौंपा जिसमें पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष तथा केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान को बम से उड़ने की धमकी देने वाले के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की गई है। बिजनौर में पार्टी के जिला अध्यक्ष रामनाथ सिंह ने राष्ट्रपति को संबोधित ज्ञापन जिलाधिकारी को सौंपा। उन्होंने कहा कि माननीय चिराग पासवान जी को दी गई धमकी भारत के



लोकतांत्रिक मूल्यों तथा दलितों की आवाज पर सीधा प्रहार है। इसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। जिला प्रवक्ता वीरेंद्र प्रताप सिंह ने इस संबंध में जानकारी देते हुए बताया कि शुक्रवार को लोक जनशक्ति पार्टी (रामविलास) के अध्यक्ष और केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री चिराग पासवान जी को बम से उड़ाने की धमकी मिली है। इसके बाद केंद्रीय मंत्री ने पुलिस विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों को इसकी सूचना दी। पुलिस ने मामले की छानबीन शुरू कर दी है। उन्होंने कहा कि पार्टी की बढ़ती लोकप्रियता तथा एक मजबूत नेता के रूप में सामने आ रहे चिराग पासवान जी के खिलाफ यह एक निंदनीय कृत्य है, जिसकी पार्टी घोर निंदा करते हुए दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग करती है। गौरतलब है कि मा चिराग पासवान ने लोकसभा चुनाव 2024 में हाजीपुर सीट से बंपर जीत हासिल की थी। वे इस वक्त प्रधानमंत्री मोदी कैबिनेट में मंत्री हैं। सक्रिय राजनीति में आने से पहले चिराग बॉलीवुड के एक्टर भी रहे हैं। सिनेमा जगत से करियर की शुरुआत करने वाले चिराग पासवान इस वक्त अपने पिता रामविलास पासवान की राजनीतिक विरासत संभाल रहे हैं। ज्ञापन देने वालों में जिला प्रधान महासचिव यादराम सिंह, जिला महासचिव हरीराज सिंह, जिला सचिव दिनेश कुमार, जिला सचिव अर्जुन सिंह सहित अनेक कार्यकर्ता उपस्थित रहे।

अधिदर्शक की पुण्यतिथि पर कवि गोष्ठी

मिर्जापुर। त्रिवेणी संस्था और हिंदी श्री साहित्य संस्थान के संयुक्त तत्वावधान में साहित्यकार व पत्रकार स्व. अधिदर्शक की प्रथम पुण्यतिथि पर विचार व काव्य गोष्ठी का आयोजन बरिया घाट स्थित द सिटी लॉन में हुआ। मुख्य अतिथि डॉ एस एन पाठक रहे व अध्यक्षता रविन्द्र कुमार पाण्डेय सरल ने किया। प्रसिद्ध नवगीतकार गणेश गंभीर, लल्लू तिवारी, राजपति ओझा और मुहीब मिर्जापुरी विशिष्ट अतिथि के रूप में मंचासीन रहे। कार्यक्रम का संचालन आनंद अमित और अनिल यादव ने संयुक्त रूप से किया। कार्यक्रम का आरंभ अतिथियों ने मां सरस्वती और स्व अधिदर्शक की प्रतिमा का माल्यार्पण करके किया।



सृष्टि राज ने मां सरस्वती की वंदना की। स्व अधिदर्शक के परिवार से उनके पुत्र कवि योगेश चतुर्वेदी ने कविता पढ़कर अपने पिता को याद किया। स्व अधिदर्शक की बहन स्नेहलता पाण्डेय व पुत्री जया पाठक, पुत्र व्धू आस्था चतुर्वेदी और पूजा पाण्डेय ने श्रद्धांजलि अर्पित किया। उपस्थित सभी साहित्यकारों ने स्व अधिदर्शक को श्रद्धांजलि अर्पित किया। अपने वक्तव्य में मुख्य अतिथि डॉ एस एन पाठक ने कहा कि स्व अधिदर्शक ने संपर्धपूर्ण जीवन व्यतीत किया लेकिन झुके नहीं। उनकी रचनाओं में उनका संपर्ष दिखाई देता है। आपके हाथ में गुलाब आए और दोस्त आनंद भवन रोता है दोनों पुस्तकों में गंभीर और समाज को राह दिखाने वाली रचनाएं हैं। रविन्द्र पाण्डेय ने कहा कि अधिदर्शक की रचनाएं हर वर्ग के लिए हैं। प्रसिद्ध नवगीतकार गणेश गंभीर ने कहा कि अधिदर्शक जी बहुत ही भावुक और स्पष्टवादी थे। प्रसिद्ध संचालक व कवि लल्लू तिवारी ने कहा कि अधिदर्शक जी एक क्रांतिकारी विचारक थे। चर्चित शायर मुहीब मिर्जापुरी ने अधिदर्शक जी के लिखे गुजलों की तारीफ की। काव्यपाठ करने वालों में केदारनाथ सविता, गुमनाम मिर्जापुरी, शिवप्रसाद द्विवेदी, आनंद अमित, श्याम अवल, सारिका चौरसिया, इरफान कुरैशी, हौसला प्रसाद मिश्र, रेखा चौरसिया, अमरनाथ सिंह, विजय श्रीवास्तव, मयंक प्रजापति शामिल थे। कार्यक्रम में प्रमुख रूप से मिमला शंकर दुबे, दीपक गुप्ता, कमलेश दुबे, चंद्रकांत तिवारी आदि उपस्थित रहे। अन्य में अनिल यादव ने सभी का धन्यवाद प्रकट किया।

सम्पादकीय.....

सुप्रीम कोर्ट से उम्मीद

भारत में मुख्यधारा का मीडिया प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की सलाह मानते हुए अब सकारात्मक रवैया अपनाने लगा है, खासकर तब, जबकि इसमें किसी भी तरह भाजपा का हित जुड़ा हो। प्रधानमंत्री बनने से पहले दिल्ली में कॉलेज छात्रों को दिए एक भाषण में अपनी सकारात्मक सोच का उदाहरण देते हुए श्री मोदी ने कहा था कि वे गिलास आधा खाली है या आध ा भरा है, इस सवाल पर कहते हैं कि गिलास पूरा भरा है, जो खाली दिख रहा है, वहां हवा भरी है। तो बस तब से देश में ऐसे ही हवा–हवाई माहौल चल रहा है। कुछ रहे न रहे, बस सब चंगा सी की उम्मीद पर देश को चलाया जा रहा है। मीडिया भी तथ्यों को न देखकर हवा–हवाई बातों को बढ़ा रहा है। जैसे गुरुवार को मीडिया ने इस बात को जोर–शोर से चलाया कि चुनाव आयोग को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। चुनाव आयोग की बिहार में मतदाता सूची गड़न पुनरीक्षण की कवायद पर शीर्ष अदालत ने कोई रोक नहीं लगाई है। लेकिन ये हवा से आधे भरे गिलास का उदाहरण है। असल बात ये है कि शीर्ष अदालत ने चुनाव आयोग से साफ तौर पर कहा है कि वह जिन 11 दस्तावेज की मांग मतदाताओं से कर रहा है, उसमें आधार कार्ड को भी शामिल किया जाए। अदालत ने चुनाव आयोग से यह भी कहा है कि आप नागरिकता के मुद्दे पर क्यों जा रहे हैं, यह गृहमंत्रालय का विषय है। कुछ मिलाकर सुप्रीम कोर्ट ने तथ्यों और तर्कों के आधार पर ही सुनवाई होने दी और उसकी अहम टिप्पणियां भी इन्हीं के आध ार पर थीं। सुप्रीम कोर्ट न पूरी तरह चुनाव आयोग के पक्ष में दिख़ा, न उसने याचिकाकर्ताओं की तरफ कोई पक्षपात दिखाया, बल्कि उसकी तटस्थता साफ नजर आई, फिर भी मीडिया में चलाए जा रहे शीर्षक यह भ्रम पैदा कर रहे हैं कि बिहार में जिस मुद्दे को लेकर 9 जुलाई को विपक्ष ने इतना बड़ा हल्ला बोल किया, उस मुद्दे पर विपक्ष को अदालत में झटका मिला है। जबकि ऐसा नहीं है। गौरतलब है कि बिहार में चुनाव से ठीक पहले चुनाव आयोग ने मतदाता सूची के स्पेशल इंटेसिव रिवीजन (एसआईआर) की कवायद शुरू की और इसके लिए केवल एक महीने का ही वक्त मतदाताओं को दिया कि वे अपने नागरिक होने का प्रमाण खुद ही पेश करें। आयोग ने 11 दस्तावेज की सूची जारी की और कहा कि इनमें से किसी को पेश करने पर ही किसी का नाम मतदाता सूची में आएगा, अन्यथा काट दिया जाएगा। आसान शब्दों में कहें तो चुनाव आयोग ने बिहार के मतदाताओं से खुद के नागरिक होने का सबूत मांगा, जबकि इसमें आधार कार्ड, राशन कार्ड और मनरेगा कार्ड को मान्यता नहीं दी, जबकि करोड़ों गरीबों के पास यही सबसे सुलभ पहचानपत्र होते हैं और इन्हें भी सरकार ही जारी करती है। इस फैसले को लोकतांत्रिक अधिकार पर सीधा हमला करते हुए चुनाव आयोग के समक्ष विपक्ष ने अपना विरोध दर्ज कराया था, फिर भी कोई समाधान नहीं निकला तो विपक्ष ने 9 जुलाई को बिहार बंद करवाया और इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे भी खटखटाए। एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स के अलावा राजद सांसद मनोज झा, तुणमूल कांग्रेस सांसद महुआ मोइत्रा, कांग्रेस के के. सी. वेणुगोपाल, राकांपा (शरद पवार गुट) की सुप्रिया सुले, भाकपा के टी. राजा, सपा के हरिंदर सिंह मलिक, शिवसेना (उद्धव ठाकरे गुट) के अरविंद सावंत, झामुमो के सरफराज अहमद, और भाकपा (माले) के दीपंकर भट्टाचार्य, इन सभी ने शीर्ष अदालत से चुनाव आयोग के आदेश को रद्द करने की मांग की है। याचिकाकर्ताओं में से एक की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता गोपाल शंकर नारायणन ने कहा कि जन प्रतिनिधित्व अधि नियम के तहत मतदाता सूची का पुनरीक्षण किया जा सकता है, लेकिन इस विशेष गहन पुनरीक्षण में कई समस्याएं हैं। उन्होंने कहा कि यह प्रक्रिया लगभग 7.9 करोड़ नागरिकों को कवर करेगी, और इसमें वोटर आईडी और आधार कार्ड जैसे दस्तावेज को भी स्वीकार नहीं किया जा रहा है। याचिकाकर्ताओं ने कहा कि वोटर लिस्ट का रिवीजन मतदाताओं पर अपनी नागरिकता साबित करने का दबाव डालता है जबकि यह काम चुनाव आयोग का है। उन्होंने कहा कि अब जब चुनाव बिल्कुल नजदीक हैं और चुनाव आयोग कर रहा है कि वह 30 दिनों में पूरी मतदाता सूची का रिवीजन करेगा। इस मामले में गुरुवार को पहली सुनवाई हुई। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस सुध ांशु धूलिया और जस्टिस जॉयमाल्य बागची की बेंच ने मामले में सुनवाई की। बेंच ने चुनाव आयोग से पूछा कि आधार कार्ड को स्वीकार क्यों नहीं किया गया। जिस पर चुनाव आयोग की ओर से पेश सीनियर वकील राकेश द्विवेदी ने जवाब दिया कि आधार कार्ड को नागरिकता का प्रमाण नहीं माना जा सकता। तब जस्टिस धूलिया ने कहा, श्लेकिन नागरिकता का निर्धारण चुनाव आयोग का नहीं, बल्कि गृह मंत्रालय का कार्यक्षेत्र है। इस पर चुनाव आयोग की ओर से जवाब दिया गया।

संयुक्त राष्ट्र के दस्तावेज ने उठायी वैश्विक कंपनियों की भूमिका पर उंगली

रेमजी बरोद

अधिकृत फिलिस्तीन में मानवाधिकारों की स्थिति पर संयुक्त राष्ट्र की विशेष रिपोर्टर, फ्रांसेस्काअल्बानीज, सत्ता के सामने सच बोलने की अवध ारणा की एक मिसाल हैं। यह श्शक्तिश् इजराइल या संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा नहीं, बल्कि एक ऐसे अंतरराष्ट्रीय समुदाय द्वारा विहित है जिसकी सामूहिक प्रासंगिकता गाजा में चल रहे नरसंहार को रोकने में दुखद रूप से विफल रही है। 3 जुलाई को संयुक्तराष्ट्र मानवाधिकार परिषद को सौंपी गयी उनकी नवीनतम रिपोर्ट, कब्जे की अर्थव्यवस्था से नरसंहार की अर्थव्यवस्था तकश्, एक भूकंपीय हस्तक्षेप का प्रतीक है। यह रिपोर्ट बेबाकी से उन कंपनियों का नाम लेती है और उन्हें दोषी ठहराती है जिन्होंने न केवल इजराइल को फिलिस्तीनियों के खिलाफ युद्ध और नरसंहार जारी रखने दिया, बल्कि उन लोगों का भी सामना करती है जो इस भयावह स्थिति के सामने चुप रहे। अल्बानीज की श्नरसंहार (एक अर्थाव्यवस्था) पर परिधद अकादमिक अभ्यास या एक मात्र नैतिक कथन से कहीं बढ़कर है, एक ऐसे विषय में जहां गाजा में सामूहिक विवेक का क्रूर परीक्षण हो रहा है। यह रिपोर्ट

कई परस्पर जुड़े कारणों से महत्वपूर्ण है। महत्वपूर्ण रूप से, यह जवाबदेही के व्यावहारिक रास्ते प्रस्तुत करती है जो केवल कूटनीतिक और कानूनी बयानबाजी से परे हैं। यह अंतरराष्ट्रीय कानून के प्रति एक नया दृष्टिकोण भी प्रस्तुत करती है, इसे एक नाजुक राजनीतिक संतुलनकारी कार्य के रूप में नहीं, बल्कि युद्ध अपराधों में मिलीभगत का सामना करने और गाजा में मौजूदा अंतरराष्ट्रीय तंत्रों की गंभीर विफलताओं को उजागर करने के एक शक्तिशाली उपकरण के रूप में प्रस्तुत करती है। इस रिपोर्ट के महत्व को समझने के लिए दो महत्वपूर्ण संदर्भ महत्वपूर्ण हैं, जिन्हें न केवल गाजा में चल रहे इजराइली नरसंहार में, बल्कि इजराइल की समग्र उपनिवे शवादी—निवासी परियोजना में भी प्रत्यक्ष कॉर्पोरेट संलिप्तता का एक तीखा अभियोग माना जाता है। सबसे पहले, वर्षों की दैरी के बाद, फरवरी 2020 में, संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिधद (यूनएच्‌आरसी) ने एक डेटाबेस जारी किया, जिसमें अधिकृत फिलिस्तीन में अवैध इजराइली बस्तियों में व्यावसायिक गतिविधि ायों में शामिल 112 कंपनियों की सूची थी। इस डेटाबेस में

कई कॉर्पोरेट दिग्गजों — जिनमें एयरबीएनबी, बुकिंग डॉट कॉम, मोटोरोला सोल्युशन, जेसीबी, और एक्सपेडिया शामिल हैं—को इजराइल को उसके सैन्य कब्जे और रंगभेद को बनाये रखने में मदद करने की गतिविधि ायों को उजागर किया गया है। यह घटना विशेष रूप से विनाशकारी थी, क्योंकि संयुक्त राष्ट्र इजराइल पर लगाम लगाने या फिलिस्तीन में उसके युद्ध अपराधों को बढ़ावा देने वालों को जवाबदेह ठहराने में लगातार विफल रहा है। यह डेटाबेस एक महत्वपूर्ण कदम था जिसने नागरिक समाजों को प्राथमिकताओं के एक विशिष्ट समूह के इर्द—गिर्द लामबंद होने की अनुमति दी, जिससे निगमों और व्यक्तिगत सरकारों पर नैतिक रूप से निर्देशित रुख अपनाने का दबाव बना। इस रणनीति की प्रभावशीलता का पता अमेरिका और इजराइल की अतिरंजित और क्रोधित प्रतिक्रियाओं से स्पष्ट रूप से चला। अमेरिका ने कहा कि यह बदनाम परिधद द्वारा आर्थिक प्रतिशोध को बढ़ावा देने का एक प्रयास था, जबकि इजराइल ने इसे दबाव के आगे शर्मनाक आत्मसमर्पण कहा। यह रिपोर्ट 7 अक्टूबर 2023 से शुरू हुआ गाजा में इजराइली नरसंहार,

नरसंहार के दौर में भूख से मर रही आबादी को भोजन उपलब्ध ा कराने की मामूली उम्मीदों को भी पूरा करने में संयुक्त राष्ट्र के सभी मौजूदा तंत्रों की घोर विफलता की एक स्पष्ट याद दिलाती है। गौरतलब है कि संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेर्रेस ने भी यही निष्कर्ष निकाला था, जिन्होंने सितंबर 2024 में कहा था कि दुनिया ने श्गजा के लोगों को निराश किया है। यह विफलता कई महीनों तक जारी रही और संयुक्त राष्ट्र द्वारा गाजा पट्टी में सहायता वितरण का प्रबंधन करने में असमर्थता के रूप में उजागर हुई, जिसने यह काम तथाकथित गाजा ह्यूमैनिटेरियन फाउंडेशन को सौंप दिया, जो एक भाड़े के सैनिकों द्वारा संचालित हिंसक तंत्र है जिसने हजारों फिलिस्तीनियों को मार डाला और घायल कर दिया है। बेशक, अल्बानीज खुद भी इसी निष्कर्ष पर पहुंच चुकी थीं, जब नवंबर 2023 में उन्होंने युद्ध को रोकने और श्निर्दोष नागरिकों के निरर्थक नरसंहार को रोकने में बेहद असफल होने के लिए अंतरराष्ट्रीय समुदाय पर निशाना साधा था। अल्बानीज की नई रिपोर्ट एक कदम और आगे जाती है— इस बार पूरी मानवता से नैतिक रुख अपनाने और उन लोगों का

सामना करने की अपील करती है जिन्होंने इस नरसंहार को संभव बनाया। रिपोर्ट में कहा गया है, निर्दोष लोगों के जीवन को नष्ट करने और उससे लाभ कमाने वाले व्यावसायिक प्रयासों को बंद किया जाना चाहिए और स्पष्ट रूप से मांग की गयी है कि कॉर्पोरेट संस्थाओं को मानवाधि ाकारों के उल्लंघन और अंतरराष्ट्रीय अपराधों में शामिल होने से इनकार करना चाहिए, अन्यथा उन्हें जवाबदेह ठहराया जायेगा। रिपोर्ट के अनुसार, नरसंहार में शामिल लोगों की श्रेणियों को हथियार निर्माता, तकनीकी कंपनियां, भवन एवं निर्माण कंपनियां, खनन एवं सेवा उद्योग, बैंक, पेंशन फंड, बीमा कंपनियां, विश्वविद्यालय और धर्मार्थ संस्थाएं बताया गया है। इनमें लॉकहीड मार्टिन, माइक्रोसॉफ्ट, अमेजन, पैलैटिर, आईबीएम और यहां तक कि डेनिश शिपिंग दिग्गज मैसंक सहित लगभग 1,000 अन्य कंपनियां शामिल हैं। यह उनकी सामूहिक तकनीकी जानकारी, मशीनरी और डेटा संग्रह ही था जिसने इजराइल को गाजा में अब तक 57,000 से ज्यादा लोगों को मारने और 1,34,000 से ज्यादा लोगों को घायल करने में सक्षम बनाया, पश्चिमी तट में रंगभेद शासन को बनाये

रखने की तो बात ही छोड़ दें। अल्बानीज की रिपोर्ट केवल इजराइल के नरसंहार सहयोगियों का नाम लेकर उन्हें शर्मिंदा करने का प्रयास नहीं करती, बल्कि हमें नागरिक होने के नाते यह बताने का प्रयास करती है समाज को यह विश्वास दिलाते हुए कि अब हमारे पास एक व्यापक संदर्भ—ढांचा है जो हमें जिम्मेदारी भरे फैले लेने, इन कॉर्पोरेट दिग्गजों पर दबाव डालने और उन्हें जवाबदेह ठहराने में सक्षम बनायेगा। अल्बानीज लिखते हैं, श्शह जारी नरसंहार एक लाभदायक उद्यम रहा है। वे इजराइल के सैन्य खर्च में भारी वृद्धि का हवाला देते हैं, जो 2023 से 2024 तक 65 प्रतिशत बढ़कर 46.5 अरब डॉलर तक पहुंच गया है। इजराइल का असीम सैन्य बजट धन का एक शक्तिशाली साधन है, जो मूल रूप से अमेरिकी सरकार द्वारा प्रदान किया जाता है, फिर अमेरिकी निगमों के माध्यम से पुनर्चक्रित किया जाता है। इस प्रकार यह धन सरकारों, राजनेताओं, निगमों और असंख्य ठेकेदारों के बीच फैल जाता है। जैसे—जैसे बैंक खाते बढ़ते हैं, और अधिक फिलिस्तीनी शव मुर्दाघरों सामूहिक कब्रों में जमा होते जाते हैं, या जबालिया और खान यूनिस की सड़कों पर बिखरे पड़े हैं।

2023 में इजराइल के सैन्य खर्च में भारी वृद्धि का हवाला देते हैं, जो 2023 से 2024 तक 65 प्रतिशत बढ़कर 46.5 अरब डॉलर तक पहुंच गया है।

निर्दोषों पर कहर और न्याय प्रणाली पर संकट

रत्नेश्वर कुमार झा

भारत में बलात्कार जैसे अपराध को लेकर सख्त कानून बनाए गए ताकि महिलाओं को न्याय और सुरक्षा मिल सके। इन कानूनों का उद्देश्य था कि पीड़िताओं को बिना किसी डर के आगे आकर न्याय मिल सके और दोषियों को कठोर सजा दी जा सके। परंतु हाल के वर्षों में एक गंभीर समस्या उभरकर सामने आई है कृ झूठे बलात्कार के मामलों का बढ़ता चलन। यह प्रवृत्ति न केवल निर्दोष लोगों की ज़िंदगियों को तबाह कर रही है बल्कि पूरे न्याय तंत्र और समाज की नैतिकता पर भी गंभीर सवाल खड़े कर रही है। सुप्रीम कोर्ट से लेकर जिला अदालतों तक ने बार–बार अपनी टिप्पणियों में इस पर चिंता व्यक्त की है और इसे कानून का घोर दुरुपयोग माना है। बलात्कार गांभीर अपने आप में इतना गंभीर और संवेदनशील होता है कि समाज, मीडिया और यहां तक कि परिवार के लोग भी आरोपी को तुरंत दोषी मान लेते हैं। कई बार इस तरह के आरोपों के चलते आरोपी की नौकरी चली जाती है, उसका सामाजिक सम्मान समाप्त हो जाता है, रिश्तेदार और मित्र उससे दूरी बना लेते हैं और मानसिक तनाव इतना बढ़ जाता है कि वह अवसाद में चला जाता है या आत्महत्या जैसा कदम उठा लेता है। सुप्रीम कोर्ट ने सुब्रतो दास बनाम

स्टेट ऑफ झारखंड (Criminal Appeal No- 1925/2014) में स्पष्ट कहा था, झूठे आरोप केवल कानून का दुरुपयोग नहीं हैं, बल्कि निर्दोष लोगों की जिंदगी बर्बाद कर देते हैं। ऐसे मामलों में शिकायतकर्ता पर भी कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। दिल्ली हाई कोर्ट ने SHAFEEQ AHMAD & ORS बनाम State of NCT of Delhi (FIR संख्या 92९2024) में कहा, झूठी शिकायतें न्याय प्रणाली को भारी बोझ देती हैं और असली पीड़िताओं को भी नुकसान पहुंचाती हैं। इन्हन टिप्पणियों में अदालतों की पीड़ा और चिंता साफ झलकती है। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो (NCRB) के आंकड़े बताते हैं कि हर साल हजारों बलात्कार के मामले दर्ज होते हैं। इन मामलों में सभी शिकायतें सच नहीं होतीं। दिल्ली में दर्ज मामलों का एक अध्ययन बताता है कि लगभग 25: मामलों में आरोपी सबूतों के अभाव में बरी हो जाते हैं। यह आंकड़ा इस ओर इशारा करता है कि कितने लोग बिना किसी अपराधों के लंबी कानूनी लड़ाई लड़ने को मजबूर होते हैं। झूठे बलात्कार मामलों के पीछे कई बार एक पूरा नेक्सस काम करता है। इसमें पीड़िता, उसके परिवारजन, कुछ वकील, दलाल और यहां तक कि पुलिसकर्मी तक शामिल होते हैं। मकसद साफ होता है कृ आरोपी से पैसे वसूलना, संपत्ति

विवाद में दबाव बनाना, या व्यक्तिगत दुश्मनी निकालना। यह नेटवर्क शिकायतकर्ता को झूठे केस दर्ज कराने और आरोपी को फंसाने में मदद करता है। जबरन समझौते के लिए ब्लैकमेलिंग, मीडिया में छवि खराब करना और सार्वजनिक दबाव बनाना कृ यह सब इस खेल का हिस्सा बन जाता है। दिल्ली हाई कोर्ट ने अपने आदेशों में कहा है कि बलात्कार के मामलों में गिरफ्तारी से पहले प्रारंभिक जांच होना अनिवार्य होना चाहिए ताकि निर्दोष लोगों को तुरंत जेल भेजने से बचाया जा सके। अदालतों ने साफ निर्देश दिया कि बलात्कार के मामलों में थ्र दर्ज होते ही आरोपी को गिरफ्तार कर लेना न्याय का मखौल है। बिहार के गया जिले की एक अदालत ने जून 2023 में एक झूठे बलात्कार केस में प्छ की धारा 211 (झूठा आरोप लगाने पर सजा) के तहत शिकायतकर्ता पर मुकदमा चलाने का आदेश दिया। इसी तरह मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने रीवा जिले के एक मामले में कहा कि मुकदमा पूरी तरह से दुर्भावना से प्रेरित था और इसका उद्देश्य केवल आरोपी को सामाजिक और मानसिक रूप से प्रताड़ित करना था। सबसे बड़ा नुकसान उन महिलाओं को होता है जो सच में यौन हिंसा की शिकार होती हैं। झूठे मामलों के कारण समाज में यह धारणा बनने लगती है

कि हर शिकायत संदिग्ध है। इससे सच्ची पीड़िताओं को न्याय मिलने में बाधा आती है, उनकी बातों पर विश्वास कम होता है और वे समाज तथा कानून दोनों से निराश होकर चुप हो जाती हैं। कानूनी दृष्टि से देखें तो प्छ की धारा 211 में झूठा आरोप लगाने पर सजा का प्रावधान है, लेकिन इसे लागू करने में अक्सर कोताही बरती जाती है। अगर यह धारा कड़ाई से लागू की जाए तो झूठे मामलों पर काफी हद तक अंकुश लगाया जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट और विभिन्न हाई कोर्ट ने समय–समय पर यह सुझाव दिया है कि झूठे मामलों में दोषी पाए गए व्यक्तियों को कड़ी सजा दी जाए ताकि दूसरों के लिए यह एक चेतावनी बने। बलात्कार जैसे अपराध में आरोपी को दोषी साबित करना आसान नहीं होता। कई बार केवल पीड़िता के बयान के आधार पर ही मुकदमा चल जाता है। अगर बयान झूठा निकला, तो आरोपी के जीवन के बर्बाद होने की भरपाई कोई नहीं कर सकता। यहां तक कि अगर अदालत से बरी भी कर दिया जाए, तब भी समाज की नजरों में वह ‘दोषी’ ही बना रहता है। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा है कि आरोप लगते ही मीडिया में आरोपी का नाम उजागर कर देना गैर—जिम्मेदाराना रवैया है। जब तक अदालत कोई अंतिम फैसला न सुना दे, तब तक

आरोपी को प्छोपी की तरह प्रस्तुत करना न्याय के खिलाफ है। मीडिया ट्रायल और सोशल मीडिया अभियानों ने स्थिति को और गंभीर बना दिया है। समाज का नजरिया भी इस स्थिति को और जटिल बना देता है। हम अक्सर ‘आरोप लगते ही दोषी मान लो’ की मानसिकता के शिकार हो जाते हैं। किसी व्यक्ति को दोषी साबित करने का काम अदालत का है, न कि समाज या मीडिया का। लेकिन कई बार आरोप लगते ही आरोपी की फोटो, नाम और निजी जानकारियां सार्वजनिक कर दी जाती हैं, जिससे उसका जीवन और परिवार दोनों तबाह हो जाते हैं। झूठे मामलों में आरोपी केवल न्यायिक प्रक्रिया का शिकार नहीं होता बल्कि सामाजिक बहिष्कार और मानसिक उत्पीड़न का भी सामना करता है। ऐसे कई मामले सामने आए हैं जहां युवक ने झूठे बलात्कार के आरोपों से तंग आकर आत्महत्या कर ली। यह स्थिति केवल व्यक्तिगत स्तर पर ही नहीं, बल्कि समाज और कानून दोनों के लिए बेहद शर्मनाक है। झूठे मामलों पर अंकुश लगाने के लिए केवल कानून कड़ा करना ही काफी नहीं है, बल्कि समाज को भी ज़िम्मेदाराना बनाना होगा। हमें यह समझना होगा कि न्याय का सिद्धांत कहता है कृ प्जब

तक दोष सिद्ध न हो जाए, तब तक व्यक्ति निर्दोष है। अगर इस सिद्धांत का पालन न किया गया, तो निर्दोषों के जीवन से खिलवाड़ होता रहेगा और असली अपराधियों को सजा दिलाना और कठिन होता जाएगा। कई बार झूठे मामलों का इस्तेमाल राजनीतिक या कारोबारी दुश्मनी निकालने के लिए भी किया जाता है। जैसे किसी सरकारी पीड़िताओं के अधिकारों पर सीधा हमला किया है। आगे बढ़ने का रास्ता क्या हो सकता है? सबसे पहले, प्रारंभिक जांच को अनिवार्य बनाया जाए और बिना ठोस सबूत के गिरफ्तारी पर रोक लगे। दूसरा, प्छ की धारा 211 को सक्रिय रूप से लागू किया जाए ताकि झूठा आरोप लगाने वालों को तुरंत सजा दी जा सके। तीसरा, मीडिया पर नियंत्रण हो और किसी भी आरोपी को पहचान केवल तभी उजागर की जाए जब अदालत उसे दोषी ठहरा दे। चौथा, समाज में इस मुद्दे पर व्यापक जागरूकता अभियान चलाया जाए ताकि लोग समझ सकें कि आरोप लगाना आसान है, पर उसका असर जीवनभर रहता है।

कहीं भारत की कमजोरियों का लाभ न उठा ले दुनिया

वर्षा भग्नाभी मिर्जा

एक राजा था। बड़े ही गाजे–बाजे के साथ उसका राज्याभिषेक हुआ था। वह दिखता तो बहुत आत्मविश्वासी था लेकिन उसे हमेशा यह डर बना रहता था कि कहीं उसका राज–पाट छिन न जाए। राजसी परिवार के वृक्ष में से कुछ के खलबली का अंदेशा भी उसे बना रहता। वह आए दिन इसी चिंता में लगा रहता और अपने दरबारियों को ऐसा करने की खुली छूट देता जिससे जनता में यह संदेश जाए कि केवल वही इस पद के सर्वथा योग्य है और शेष सब नाकारे और निकम्मे हैं। राजा के इस डर से दरबारी और उनके जानने वाले तो वान्िकफ थे ही लेकिन अब तो दुश्मनों को भी खबर हो गई थी। उन्होंने भी प्रमाण लिया था कि राजा डरता है और इसका फायदा उन्हें मिल सकता है। राजा के गद्दी बचाने के तमाम हथकंडों को उसकी रियाया भी समझ रही थी लेकिन उसे अपने राज्य की फिक्र थी। दुश्मनों को भला प्रजा की क्या परवाह होती? वह बस केवल मौके की तलाश रहते। राजा की सत्तालिप्सा और डर उन्हें बैठे–बिठाए यह सब उपलब्ध करा रहा था। दरबारी और चांदूकार अपना रौब–दाब बनाए रखने के लिए किसी भी हद तक चले जाते थे बिना इस बात की परवाह किये कि इस राजा के पुरखों ने राजदंड के साथ कुछ नियम कायदे भी जोड़े थे। यहां राजा कृष्णदेव राय की तरह न कोई तेनालीराम था और न अकबर की तरह कोई बीरबल। चापलूस किस्म के कुछ तो राजा को खुश करने के लिए कुछ ज्यादा ही घी का इस्तेमाल कर लेते थे जो अब बह कर राज्य की सीमा से आने लगा था। इन दो—तीन दिनों में जो हुआ वह गौर करने लायक है। बिहार के मतदाताओं की समस्या, महाराष्ट्र में भाषा का पासा आदि तो

जारी है ही, फिलहाल देश की छवि को जो नुकघसान उद्योगपति और टिटटर (अब एक्स) के मालिक एलन मस्क ने पहुंचाया है, वह बताता है कि अगर सरकार प्रेस विरोधी सोच रखती है तो फिर आपका इस्तेमाल यूं भी हो सकता है। एलन मस्क की टीम ने शएक्स पर लिखा कि बीते सप्ताह भारत सरकार ने शएक्स पर मौजूद 2 हजार 35 एकाउंट्स बंद कर देने के लिए कहा जिसमें अंतरराष्ट्रीय न्यूज एजेंसी रायटर्स के दो अकाउंट भी शामिल थे। देश दुनिया में हल्ला मचना ही था। मचा भी, कि भारत में अभिव्यक्ति की आजादी का गला यूं घोंटा जा रहा है। देश तो जानता है कि इस सरकार को अपनी शान के खिलाफ एक पोस्टर, बयान, टवीट और गीत तो क्या मसखरों का मजाक भी मंजूर नहीं है। बड़े उद्योगपति मस्क जो भारत में सैटेलाइट इंटरनेट स्टारलैंक को लाने की तैयारी लगभग कर चुके हैं, उनके द्वारा न्यूज एजेंसी रायटर्स के बारे में ऐसा बयान आते ही सरकार तो जैसे सफाई देने की मुद्रा में ही आ गई। एक्स ने इन अकाउंट्स के फिक्र के साथ लिखा कि यह ऑनगोइंग प्रेस सेंसरशिप इन इंडिया यानी भारत में जारी प्रेस सेंसरशिप के हालात जाहिर करता है। इसके बाद सरकार तुरंत हरकत में आई और कहा कि हमने 3 जुलाई को कोई नया आदेश नहीं दिया। रायटर्स को ब्लॉक होने के बाद हमने तुरंत एक्स का ध्यान इस तरफ दिलाया और उसने तकनीकी कारणों का हवाला देते हुए काफी समय खराब कर दिया और फिर पूरे 21 घंटों बाद इस प्रतिबंध को हटाया। ऐसा 5 जुलाई को इलेक्ट्रॉनिक और सूचना तकनीकी मंत्रालय के प्रवक्ता ने कहा था। इसके पन्हिले 3 जुलाई को एक्स ने अपने वैश्विक सरकारी मामलों के हैंडल पर लिखा कि भारत ने

2355 खातों को, जिनमें रायटर्स (ढाई करोड़ फॉलोवर्स) और रायटर्स वर्ल्ड (71 करोड़) शामिल थे, आईटी की धारा 69 एश्ए के तहत नोटिस जारी करने के बाद किया गया। पोस्ट में लिखा गया कि जब पूरी दुनिया में विरोध हुआ तब एजेंसी के दोनों खातों को बहाल करने का अनुरोध किया गया। एक्स का यह भी कहना था कि भारत सरकार के कानून उन्हें यूजर्स को खाते जारी रखने से रोकते हैं। टीम ने एक पोस्ट में लिखा—एक्स सभी उपलब्ध कानूनी विकल्प तलाश रहा है लेकिन उसके हाथ बंधे हुए हैं। मौजूदा भारतीय कानून इन कार्यकारी आदेशों के विरुद्ध विधिक चुनौती देने से रोकते हैं। हम प्रभावित यूजर्स से आग्रह करते हैं कि वे अदालतों के माध्यम से कानूनी राहते पाने का प्रयास करें। यहां यह जानना भी दिलचस्प होगा कि अगले ही दिन यानी 10 जुलाई को भारत के समाचारपत्रों में रायटर्स न्यूज एजेंसी के हवाले से ही यह खबर भी छपती है कि एलन मस्क की कंपनी स्टारलैंक को भारत में सैटेलाइट इंटरनेट सर्विस शुरू करने के लिए अंतिम मंजूरी मिल गई है। इससे पहले इसी साल मार्च में भी एलन मस्क की कंपनी एक्स ने कर्नाटक उच्च न्यायालय में सरकार को चुनौती देते हुए कहा था कि —भारत में अधिकारियों को यह शक्ति दे दी गई है कि वे कभी भी सोशल मीडिया के खातों पर प्रतिबंध लगाने का डंडा चला सकते हैं। यह घटना बताती है कि भारत के नेताओं की राजनीतिक असुरक्षा की भनक दुनिया के चतुर सुजानों को लग चुकी है और वे मौका मिलने पर अपने हित में हालात को भुना सकते हैं। वैसे यह गफलत ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारत विरोधी बयानबाजों से निपटने के लिए और प्राकृतास्तानी खातों को प्रतिबंधित करने के सिलसिले से शुरू हुई जिसमें शायद समाचार

एजेंसी रायटर्स भी शामिल हो गई। बहरहाल भारत में प्रतिबंधों और प्रेस की आजादी को कुचलने का सिलसिला कोई नया नहीं है। पत्रकारों के घर छापे, विदेशी पत्रकारों को देश से निकलने के कई मामले सामने आए हैं। दिल्ली में काम कर रही फ्रांसिसी रिपोर्टर वेनेसा डोमिएक के साथ भी यही हुआ। उन्हें जबरदस्ती देश से बाहर भेज दिया गया जबकि वे 23 सालों से भारत में पत्रकारिता कर रही थीं और एक भारतीय से ही उन्होंने शादी भी की थी। सरकार का कहना था की वे भारत के प्रति पक्षपाती और नकारात्मक रवैया रखती थीं। बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री इंडियारू द मोदी क्वेश्चनरज जो 2002 के गुजरात दंगों से लेकर भारत में मुसलमानों के हालात और नरेंद्र मोदी से उनके रिश्तों पर आध ारित है, उसे भी बैन कर दिया गया था। बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री के पहले अंक के रिलीज होने के बाद ही भारत सरकार ने इसे एकतरफा दुष्प्रचार और औपनिवेशिक मानसिकता बताकर प्रतिबंधिात कर दिया था। ऐसा तब था जब डॉक्यूमेंट्री को बीबीसी ने भारत में रिलीज ही नहीं किया था। फिर भी सरकार ने रोक लगाई जिससे डॉक्यूमेंट्री को और प्रचार मिला था। सरकार के चलाने वालों की असुरक्षा जब–तब सामने आ ही जाती है। कभी न्यूज एजेंसी तो कभी पत्रकार, कभी छात्र और यहां तक कि जज भी उसके निशाने पर आ जाते हैं। तत्कालीन कानून मंत्री किरण रिजिजू ने तो सेवानिवृत्त जजों को ही एंटी इंडिया गैंग का हिस्सा बता दिया था। उन्होंने कहा था—कुछ रिटायर्ड जज ऐसे हैं जो एंटी इंडिया गैंग का हिस्सा हैं। ये लोग चाहते हैं कि भारतीय न्यायपालिका विपक्षी दल की तरह काम करे। कुछ लोग तो कोर्ट में जाकर यह तक कहते हैं कि सरकार की नीतियों को बदला जाए।

अजय देवगन-काजोल की फिल्म राजू चाचा

जब सितारों से सजी ये फिल्म बनी साल 2000 की सबसे बड़ी फ्लॉप, करोड़ों का नुकसान



बॉलीवुड की सबसे चर्चित जोड़ियों में से एक अजय देवगन और काजोल ने अपने करियर में कई फिल्मों में साथ काम किया है, लेकिन 25 साल पहले यानी साल 2000 में रिलीज हुई उनकी एक फिल्म ने न सिर्फ दर्शकों को निराश किया, बल्कि मेकर्स को भी बड़ा झटका दिया। इस फिल्म का नाम था ‘राजू चाचा’, जिसे खुद अजय देवगन ने प्रोड्यूस किया था। इस मल्टीस्टारर फिल्म में काजोल के साथ बॉलीवुड के दिग्गज कलाकार संजय दत्त, ऋषि कपूर और जॉनी लीवर जैसे नाम भी शामिल थे। इसके बावजूद यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर बुरी तरह से फ्लॉप साबित हुई और साल 2000 की सबसे बड़ी असफल फिल्मों की लिस्ट में शामिल हो गई। ‘राजू चाचा’ को लेकर शुरुआत में काफी उम्मीदें थीं। फिल्म की स्टारकास्ट बेहद दमदार थी, अजय देवगन, काजोल, संजय दत्त, ऋषि कपूर और जॉनी लीवर जैसे

कलाकारों ने इसमें अहम भूमिकाएं निभाईं। फिल्म का निर्देशन अनील देवगन ने किया था और इसे अजय देवगन और उनके पिता वीरू देवगन ने मिलकर प्रोड्यूस किया था। कहानी एक सिंगल फादर के तीन बच्चों और एक अनजान व्यक्ति की है, जो खुद को उनका श्वाचाश बताकर उनकी संपत्ति हड़पने की योजना बनाता है, लेकिन बाद में उसके इरादे बदल जाते हैं। फिल्म में भावनाओं, ड्रामा, एक्शन और मस्ती का तड़का था, लेकिन पटकथा और निर्देशन दर्शकों को लुभाने में नाकाम रहे। फिल्म को बनाने में तकरीबन 25 करोड़ रुपये खर्च किए गए थे, जो उस समय की फिल्मों के हिसाब से एक बड़ा बजट माना जाता था। लेकिन फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर केवल 20 करोड़ रुपये की कमाई कर पाई। यानी फिल्म को लगभग 5 करोड़ रुपये का सीधा घाटा हुआ। इस भारी नुकसान का असर अजय देवगन

पर भी साफ देखा गया। काजोल ने एक पुराने इंटरव्यू में बताया था कि इस फिल्म की असफलता ने अजय को अंदर तक झकझोर दिया था और इससे उबरने में उन्हें काफी समय लगा। जहां एक तरफ फिल्म की भव्यता और कलाकारों की लोकप्रियता को देखकर दर्शकों ने इसे लेकर उम्मीदें बांध ली थीं, वहीं दूसरी ओर इसके कमजोर कंटेंट और खराब निर्देशन ने इन्हीं उम्मीदों को तोड़ दिया। फिल्म को मात्र 5.1६10 की रेटिंग मिली है, जो यह दर्शाता है कि यह दर्शकों के दिलों में कोई खास जगह नहीं बना सकी। भले ही फिल्म का कॉन्सेप्ट इमोशनल और पारिवारिक था, लेकिन इसकी स्क्रिप्ट कमजोर और बिखरी हुई थी। यह अनील देवगन की शुरुआती निर्देशकीय फिल्मों में से एक थी, जिसमें अनुभव की कमी साफ नजर आई। फिल्म की स्टारकास्ट और प्रमोशन से जो उम्मीदें बनी थीं, फिल्म उन्हें पूरा नहीं कर पाई।

रवीना टंडन ने की महाअवतार नरसिम्हा की सराहना, पोस्टर शेयर कर दिखाया जोश



महाअवतार नरसिम्हा का जो ट्रेलर हम सब इतने समय से इंतजार कर रहे थे, वो आखिरकार रिलीज हो गया है और कहना पड़ेगा, ये वाकई लाजवाब है। इसकी भव्यता, विजुअल्स और कहानी कहने का अंदाज इतना दमदार है कि इसे देखकर रोंगटे खड़े हो जाते हैं। सबसे खास बात ये रही कि ट्रेलर के साथ मेकर्स ने महा अवतार सिनेमैटिक यूनिवर्स की शुरुआत का भी ऐलान कर दिया है। यानी अब सिर्फ एक फिल्म नहीं, बल्कि इस कहानी की कई किस्तें आने वाली हैं, जो और भी ज्यादा रोमांचक होंगी। ट्रेलर आते ही लोगों की एक्साइटमेंट एकदम अलग ही लेवल पर पहुंच गई है। अब तो हर किसी को बस इस फिल्म के थिएटर्स में आने का इंतजार है। महाअवतार नरसिम्हा को लेकर बढ़ते उत्साह के बीच मशहूर अभिनेत्री रवीना टंडन भी इस फिल्म को लेकर अपनी खुशी जताते नजर आईं। उन्होंने अपने सोशल मीडिया पर फिल्म का पोस्टर शेयर किया, जो इस बात का सबूत है कि इस फिल्म को लेकर लोगों में कितनी जबरदस्त हलचल है। ये सिर्फ दर्शक ही नहीं, बल्कि सेलिब्रिटीज भी हैं जो इस फिल्म के रिलीज का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। ट्रेलर ने जो प्रभाव डाला है, वो वाकई ऐतिहासिक है क्योंकि हर कोई बस इसी की बात कर रहा है और उत्साह हर दिन नई ऊँचाइयों

को छू रहा है। होम्बले फिल्म्स और क्लीम प्रोडक्शन्स ने मिलकर इस ग्रैंड एनिमेटेड फ्रैंचाइजी की आधिकारिक लाइनअप जारी कर दी है, जो अगले एक दशक तक भगवान विष्णु के दस दिव्य अवतारों की गाथा बताएगी। इस यूनिवर्स की शुरुआत होगी महावतार नरसिम्हा (2025) से, इसके बाद आएंगे महावतार परशुराम (2027), महावतार रघुनंदन (2029), महावतार द्वारकाधीश (2031), महावतार गोकुलानंद (2033), महावतार कल्कि पार्ट 1 (2035) और महावतार कल्कि पार्ट 2 (2037)। ये यूनिवर्स भारतीय माइथोलॉजी को नई तकनीक और भव्यता के साथ दर्शकों के सामने पेश करेगा। महावतार नरसिम्हा का डायरेक्शन अश्विन कुमार ने किया है, और इसे शिल्पा धवन, कुशल देसाई, और चौतन्य देसाई ने कलीम प्रोडक्शंस के तहत प्रोड्यूस किया है। होम्बले फिल्म्स के साथ मिलकर, जो अपनी आकर्षक कंटेंट के लिए जानी जाती है, यह पार्टनरशिप अलग- अलग एंटरटेनमेंट प्लेटफॉर्मस के जरिए एक सिनेमाई मास्टरपीस पेश करने का लक्ष्य रखती है। इस फिल्म को शानदार विजुअल्स, सांस्कृतिक विविधता, बेहतरीन फिल्म तकनीक, और मजबूत कहानी के साथ, 3ड और पांच भारतीय भाषाओं में 25 जुलाई 2025 को रिलीज किया जाएगा।



पश्चिम में मेरा काम शुरुआती दौर में, आगे क्या होता है यह देखने के लिए उत्साहित हूं- प्रियंका चोपड़ा

प्रियंका चोपड़ा जोनास एक भारतीय अभिनेत्री और निर्माता हैं। मिस वर्ल्ड 2000 प्रतियोगिता की विजेता, चोपड़ा भारत की सबसे अधिक भुगतान पाने वाली अभिनेत्री हैं और उन्हें दो राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार और पांच फिल्मफेयर पुरस्कारों सहित कई पुरस्कार मिले हैं। बॉलीवुड में शानदार करियर के बाद अब पश्चिम में अपने फिल्मी सफर को विस्तार देने पर केंद्रित कर रहीं अभिनेत्री प्रियंका चोपड़ा जोनास ने कहा है कि सफलता एक निरंतर विकास की प्रक्रिया है। अपनी नवीनतम हॉलीवुड फिल्म “हेड्स ऑफ स्टेट” में प्रियंका ने एमआई6 एजेंट नोएल बिसेट की भूमिका निभाई है जिसका अतीत ब्रिटेन के प्रधानमंत्री सेम क्लार्क (इड्रिस अल्बा) से जुड़ा है। फिल्म में जब सैम और नवनिर्वाचित अमेरिकी राष्ट्रपति विल डेरिंगर (अभिनेता जॉन सीना) पर नाटो सम्मेलन से पहले हमला होता है, तो बिसेट को उनकी सुरक्षा का जिम्मा सौंपा जाता है।

प्रियंका ने यहां ‘पीटीआई’ को दिए साक्षात्कार में कहा, “यह निस्संदेह एक निरंतर विकास की यात्रा है। जब मैंने 2002 में अपनी पहली फिल्म की थी, तब मैंने कभी सोचा नहीं था कि एक दिन मैं यहां पर पहुंचूंगी। लेकिन पश्चिम में मेरा काम अभी शुरुआती दौर में है। भारत में मेरा एस समृद्ध फिल्मी सफर रहा है, जहां मैंने अलग-अलग तरह की भूमिकाएं निभाई हैं और बेहतरीन कलाकारों व फिल्मकारों के साथ काम करने का अवसर मिला है।” उन्होंने कहा, “इसलिए मैं अंग्रेजी की फिल्मों में भी अलग-अलग तरह की भूमिकाएं निभाना चाहती हूं। मुझे लगता है कि अभी बहुत कुछ करना है, बहुत कुछ तलाशना है और मैं यह देखने के लिए उत्साहित हूं कि आगे क्या होगा।” उन्होंने कहा, मैं अपने किये काम पर गर्व करना चाहती हूँ। मैं ऐसी भूमिकाएं निभाने की कोशिश करती हूँ जिनमें क्षमता हो, जो मजबूत हों और जिनका फिल्म में कोई मकसद हो, न कि वे केवल सजावटी हों। प्रियंका ने हॉलीवुड शो “सिटोडेल” के साथ-साथ “बेवॉच”, “ए किड लाइक जेक”, “द मैट्रिक्स रिसरेक्शंस” और “लव अगेन” जैसी फिल्मों में प्रभावशाली किरदार निभाए हैं। प्रियंका की ओटीटी मंच ‘प्राइम वीडियो’ पर नयी फिल्म “हेड्स ऑफ स्टेट” आई है। यह एक एक्शन कॉमेडी फिल्म है, जिसमें वह हॉलीवुड सितारों इड्रिस एल्बा और जॉन सीना के साथ अभिनय करती हुई नजर आ रही हैं।



कंगना रनौत ने दिलजीत दोसांझ के पाकिस्तानी एक्ट्रेस को कास्ट करने पर किया रिएक्ट

अभिनेता-गायक दिलजीत दोसांझ को अपनी फिल्म सरदार जी 3 में पाकिस्तानी कलाकार हनिया आमिर के साथ काम करने के लिए कड़ी आलोचनाओं का सामना करना पड़ रहा है। अब टाइम्स नाउ से बात करते हुए, अभिनेत्री कंगना रनौत ने इस पर प्रतिक्रिया व्यक्त की और कहा कि कुछ लोगों का वास्तव में अपना एजेंडा होता है। कंगना रनौत ने कहा कि राष्ट्र निर्माण में हर कोई एक हितधारक है। मैंने इन लोगों के बारे में काफी कुछ कह दिया है। हमारी बातचीत की शुरुआत में, मैंने बताया था कि हमें राष्ट्र निर्माण की भावना रखनी चाहिए-हर कोई एक हितधारक है। हम ऐसी भावना क्यों नहीं रखते? दिलजीत अपना अलग रास्ता क्यों अपना रहे हैं? किसी और क्रिकेटर का अपना रास्ता क्यों होना चाहिए? यहाँ तक कि एक सैनिक का भी राष्ट्रवाद का अपना रास्ता होता है। उन्होंने आगे कहा कि घ्टमें सभी को एक साथ लाने की कोशिश करनी चाहिए। उन्होंने कहा, फ्लोई ऐसा कर रहा है, बेचारा सैनिक राष्ट्रवाद का रास्ता अपना रहा है, बेचारा राजनेता राष्ट्रवाद का रास्ता अपना रहा है। कुछ लोगों का सचमुच अपना एजेंडा है। मैं यह नहीं कह रही कि यह अस्वाभाविक है, लेकिन हमें सभी को एकजुट करने का प्रयास करना चाहिए। हमें एकजुट करने का प्रयास करना चाहिए, और यह तभी होगा जब हम इन राजनेताओं के सामने यह विचार रखेंगेय यह आपका काम है।

सक्षिप्त



अदाणी समूह कोलकाता में ऐतिहासिक कुम्हारटुली घाट का जीर्णोद्धार करेगा

कोलकाता की सांस्कृतिक विरासत को संरक्षित करने की दिशा में कदम बढ़ाते हुए अदाणी समूह ने ऐतिहासिक कुम्हारटुली घाट का पुनरुद्धार करने के लिए श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट, कोलकाता (एसएमपीके) के साथ हाथ मिलाया है। अधिकारियों ने शुक्रवार को यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि कुम्हारटुली के लोग कई पीढ़ियों सेमूर्ति बनाने की अपनी परंपरा के लिए प्रसिद्ध है। इस पहल का उद्देश्य घाट को अधिक स्वच्छ, सुरक्षित तथा कारीगरों, स्थानीय लोगों और पर्यटकों के लिए अधिक सुलभ बनाना है, जिससे शहर के सबसे प्रतिष्ठित नदी तटों में से एक को नया जीवन मिल सके। बंदरगाह की ‘स्वच्छता’ पहल के तहत हुगली नदी के किनारे ऐतिहासिक घाट के पुनर्विकास, जीर्णोद्धार और सौंदर्यीकरण के लिए एसएमपीके और अदाणी पोर्ट्स एंड स्पेशल इकोनॉमिक जोन लिमिटेड (एपीएसईजेड) ने शुक्रवार को एक समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए। यह समझौता एक सार्वजनिक–निजी भागीदारी (पीपीपी) को दर्शाता है जिसका उद्देश्य पर्यावरणीय अनुकूल को बढ़ाना और नागरिक जिम्मेदारी को ध्यान में रखते हुए विरासत–अनुरूप पुनर्विकास के माध्यम से सांस्कृतिक स्थल में बदलाव लाना है। एसएमपीके के चेयरमैन रथेंद्र रमन ने कहा, “यह सिर्फ एक जीर्णोद्धार परियोजना नहीं है, बल्कि बंगाल की कलात्मक विरासत का पुनरुद्धार है।” एपीएसईजेड के कारोबार विकास अध्यक्ष सुब्रत त्रिपाठी ने कहा, “कोलकाता की पहचान से भावनात्मक रूप से जुड़े एक स्थान के जीर्णोद्धार में मदद करना सम्मान की बात है। यह स्थान एक पर्यटन स्थल के रूप में कोलकाता के लिए गौरव की बात होगी।

स्विट्जरलैंड ने भारत–ईएफटीए व्यापार समझौते को मंजूरी दी, अक्टूबर में लागू होने की उम्मीद

स्विट्जरलैंड ने आखिरकार भारत और यूरोपीय मुक्त व्यापार संघ (ईएफटीए) के बीच ऐतिहासिक व्यापार समझौते को मंजूरी देने की प्रक्रिया पूरी कर ली है। इससे व्यापार बाधाएं कम होंगी और स्विट्जरलैंड से निर्यात के लिए भारतीय बाजार काफी हद तक खुल जाएगा। भारत में स्विट्जरलैंड की राजदूत माया तिस्साफी ने स्विट्जरलैंड द्वारा इस व्यापार समझौते को मंजूरी को भारत के साथ अपने देश के द्विपक्षीय संबंधों में एक ‘मील का पत्थर’ बताया। राजदूत ने पीटीआई–को बताया कि व्यापार और आर्थिक साझेदारी समझौता (टीईपीए) अक्टूबर में लागू होने की उम्मीद है। इस व्यापार समझौते के तहत, आयरलैंड, लिशटेंस्टीन, नॉर्वे और स्विट्जरलैंड जैसे ईएफटीए देश अगले 15 वर्षों में भारत में 100 अरब डॉलर का निवेश करने की योजना बना रहे हैं। आयरलैंड, लिशटेंस्टीन और नॉर्वे पहले ही इस व्यापार समझौते को मंजूरी दे चुके हैं। मार्च में, चार देशों के इस यूरोपीय समूह ने लगभग 16 वर्षों की बातचीत के बाद भारत के साथ टीईपीए पर हस्ताक्षर किए। तिस्साफी ने शुक्रवार को कहा, “कल आधी रात (स्विस समयानुसार) को, ईएफटीए–भारत टीईपीए के लिए जनमत संग्रह की समय सीमा आधिकारिक रूप से समाप्त हो गई। जनमत संग्रह न होने के कारण, स्विस जनता ने इस समझौते पर अपनी मौन स्वीकृति व्यक्त कर दी है।” स्विट्जरलैंड द्वारा व्यापार समझौते को मंजूरी स्विस काउंसिल ऑफ स्टेट्स से स्वीकृत होने के सात महीने से अधिक समय मिली। उन्होंने कहा, “टीईपीए हमारे देशों के बीच दीर्घकालिक सहयोग का मार्ग प्रशस्त करता है। शुल्क में कमी के अलावा, यह सीमा शुल्क प्रक्रियाओं को सुव्यवस्थित करने, बौद्धिक संपदा सुरक्षा को बढ़ाने और स्थायी कारोबार प्रक्रियाओं के लिए एक ढांचा स्थापित करने में मदद करेगा।” उन्होंने कहा कि सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि ईएफटीए के सदस्य देश 15 वर्षों में भारत में 100 अरब डॉलर का निवेश करेंगे तथा दस लाख नौकरियां पैदा करेंगे। उन्होंने कहा कि यह सभी संबंधित देशों के लिए ‘फायदे वाली स्थिति’ होगी। वर्तमान में, स्विट्जरलैंड भारत में 12वां सबसे बड़ा निवेशक है।

सोशल नेटवर्किंग साईट ‘एक्स’ ने भारत में सदस्यता शुल्क 48 प्रतिशत तक घटाया

सोशल नेटवर्किंग मंच ‘एक्स’ ने भारत में खाता धारकों के लिए सदस्यता शुल्क को 48 प्रतिशत तक घटा दिया है। इसके पोर्टल पर यह जानकारी दी गई है। एलन मस्क की अगुवाई



वाली सोशल मीडिया कंपनी ने मोबाइल ऐप के लिए ‘प्रीमियम’ खाता का सदस्यता शुल्क मासिक आधार पर 900 रुपये से लगभग 48 प्रतिशत घटाकर लगभग 470 रुपये कर दिया है। ‘एक्स’ में ‘प्रीमियम’ और ‘प्रीमियम–प्लस’ सेवा के ग्राहकों को उनके नाम या आईडी के बगल में एक ‘चेकमार्क’ मिलता है। इसी तरह, ‘एक्स’ ने वेबसाइट खातों के लिए प्रीमियम ग्राहक शुल्क 650 रुपये से लगभग 34 प्रतिशत घटाकर 427 रुपये कर दिया है। कंपनी ने अपने हैंडल पर सामान्य ग्राहक के लिए मासिक शुल्क को 243.75 रुपये से 30 प्रतिशत घटाकर 170 रुपये कर दिया है। सामान्य खाते का वार्षिक सदस्यता शुल्क लगभग 34 प्रतिशत घटाकर 1,700 रुपये कर दिया गया है जो पहले 2,590.48 रुपये था। इसी तरह ‘प्रीमियम प्लस’ सदस्यता का मोबाइल संस्करण उपयोगकर्ताओं को करीब 26 प्रतिशत कम 2,570 रुपये पर दिया जा रहा है जो पहले 3,470 रुपये था।

ड्यूक बॉल को लेकर फिर हंगामा, अंपायर से भिड़े गिल, कड़ी आलोचना के बाद निर्माता बदलाव के लिए तैयार

लंदन। भारत और इंग्लैंड के बीच जारी पांच मैचों की टेस्ट सीरीज का तीसरा मुकाबला लॉर्ड्स में खेला जा रहा है। इस मैच में एक बार फिर ड्यूक बॉल को लेकर विवाद हुआ है। शुक्रवार को महज 10 ओवर के बाद ही गेंद बदलनी पड़ी, जिस पर भारतीय खिलाड़ियों ने नाराजगी जताई। कप्तान शुभमन गिल और मोहम्मद सिराज की अंपायर से बहस भी हुई। अब इस मामले पर ड्यूक बॉल की निर्माता कंपनी के मालिक दिलीप जाजोदिया का बयान आया है। उन्होंने कहा कि इंग्लैंड में असामान्य रूप से गर्म मौसम और मौजूदा समय में बल्लेबाजों के आक्रामक खेल को ध्यान में रखते हुए उनकी कंपनी सुधार करने के लिए हमेशा तैयार रहती है।

10 ओवर के खेल के बाद गेंद बदलने से भारतीय खिलाड़ी नाराज

लॉर्ड्स में खेले जा रहे तीसरे टेस्ट मैच के दूसरे दिन सुबह के सत्र में दो बार गेंद को बदला गया। महज 10 ओवर के खेल के बाद गेंद को दोबारा बदलने को लेकर भारतीय खिलाड़ियों में रोष दिखा।

जाजोदिया ने समाचार एजेंसी पीटीआई से कहा, श्विस् क्रिकेट में केवल तीन मान्यता प्राप्त निर्माता हैं (ड्यूक्स, एसजी और कूकाबुरा)। क्रिकेट गेंद बनाना आसान नहीं है। यह अगर आसान होता, तो दुनिया भर में सैकड़ों निर्माता होते। इसलिए मुझे लगता है कि खिलाड़ियों को यह समझने की जरूरत है कि हम हाथ पर हाथ धरे बैठे नहीं हैं। हम अपनी पूरी कोशिश कर रहे हैं। अगर कोई समस्या है तो उसकी समीक्षा की जाएगी और हम उसका हल निकालने की कोशिश करेंगे। चाहे वह चमड़े की खराबी हो या किसी और चीज की। हम इसकी जांच करेंगे। मैं आराम से बैठा सिगार नहीं पी रहा हूँ।श उन्होंने कहा, शखिलाड़ी मेरी क्रिकेट गेंद की आलोचना कर सकते हैं। मैं भी खराब शॉट या खराब गेंद के लिए उनकी आलोचना कर सकता हूँ। आप जानते हैं मेरा क्या मतलब है? आपको समझदार होना होगा।श

गिल और पंत ने दूसरे टेस्ट के बाद भी उठाए थे सवाल मौजूदा सीरीज के दूसरे मुकाबले के बाद भारतीय टेस्ट टीम के कप्तान शुभमन गिल और उपकप्तान ऋषभ पंत ने



गेंद के इतनी जल्दी नरम होने और आकार बदलने पर निराशा व्यक्त की थी। अपने टेस्ट करियर में 604 में से ज्यादातर विकेट ड्यूक बॉल से लेने वाले इंग्लैंड के पूर्व तेज गेंदबाज स्टुअर्ट ब्रॉड ने भी तेजी से खराब हो रही गेंद के खिलाफ बात की। इस पर जाजोदिया ने कहा, सुपरस्टार (बड़े खिलाड़ी) बहस कर सकते हैं। मुझे वही बनाना होगा जो वे चाहते हैं। मैं बस इतना ही कह सकता हूँ। आलोचना करना बहुत आसान है।

ड्यूक बॉल निर्माता कंपनी के मालिक का बयान जाजोदिया से जब इस गेंद

के जल्दी खराब होने के बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा, श्इस पर मौसम का बड़ा असर होता है। क्रिकेट खेलने का तरीका और बल्ले का प्रकार बदल रहा है। खिलाड़ी शॉट में ज्यादा ताकत का इस्तेमाल कर रहे हैं। गेंद समय–समय पर बाउंड्री के बाहर कठोर चीजों से टकराती है। ऐसे में भी यह गेंद 80 ओवर तक चलती है और यह एक चमत्कार की तरह है। ड्यूक गेंद पर लेकर ईसीबी की नाराजगी के बारे में पूछे जाने पर उन्होंने कहा, नहीं, कोई तात्कालिक प्रतिक्रिया नहीं मिली है। हम एक टेस्ट श्रृंखला के बीच में हैं। मैं पूरे सम्मान के

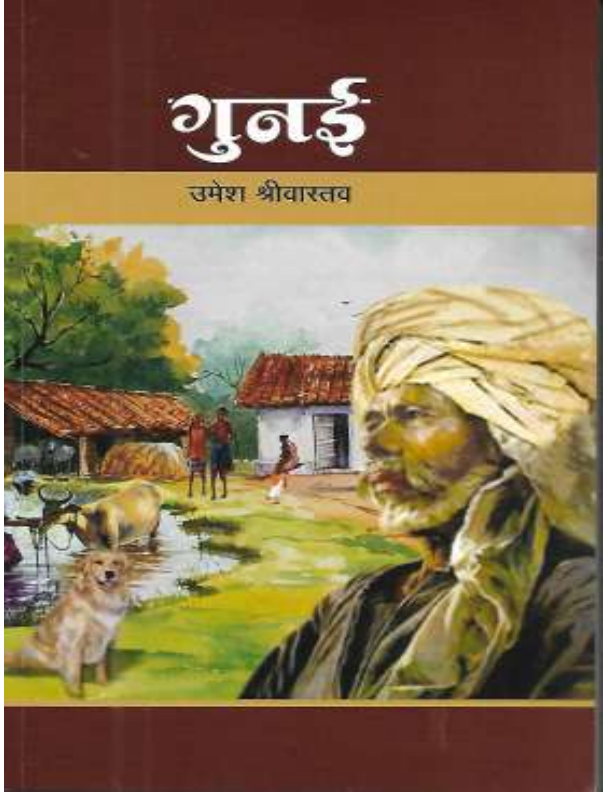
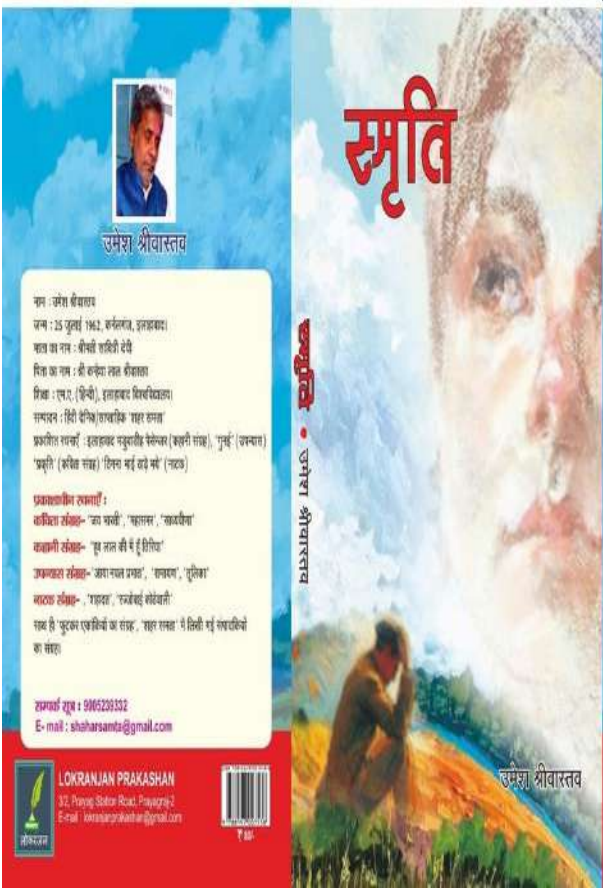
साथ कह रहा हूँ कि पिछले मैचों में दो नतीजे आए हैं। इसमें भारत ने एक मैच जीता है। कप्तान गिल ने किसी भी अन्य खिलाड़ी से अधिक रन बनाए हैं। दो गेंदबाजों ने छह विकेट लिए। तो मैं बस यही कह सकता हूँ कि असुविधा के लिए मुझे खेद है लेकिन कम से कम आप क्रिकेट तो खेल रहे हैं।

भारत में दिया जाएगा ड्यूक बॉल को अंतिम रूप भारत में घरेलू और अंतरराष्ट्रीय दोनों स्तरों पर एसजी टेस्ट बॉल का उपयोग किया जाता है। जाजोदिया का मानना है कि भारत जैसे विशाल

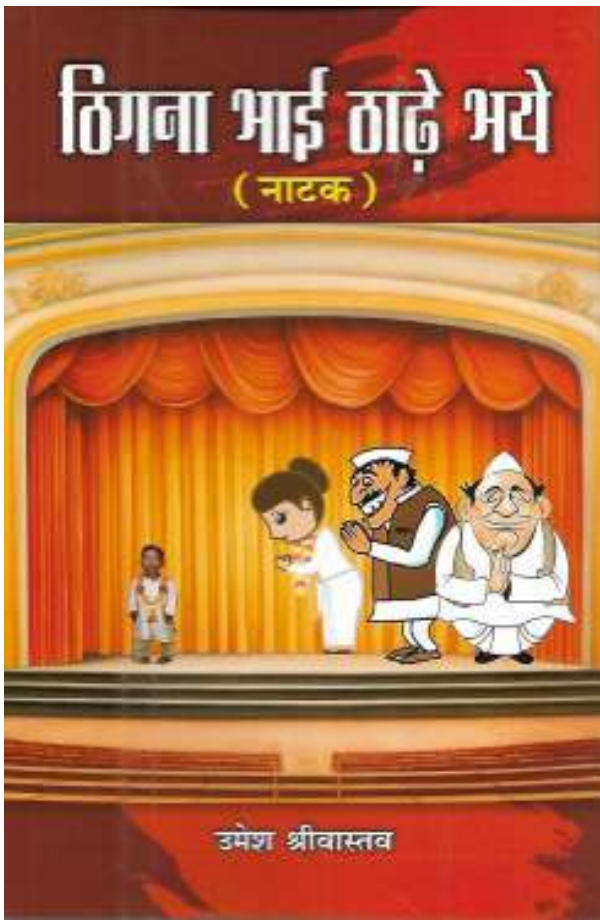
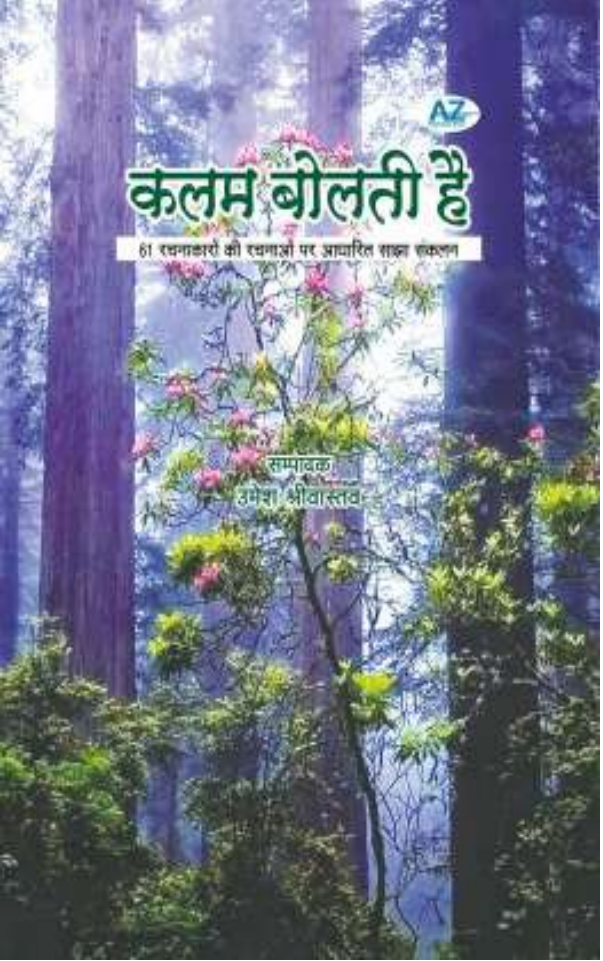
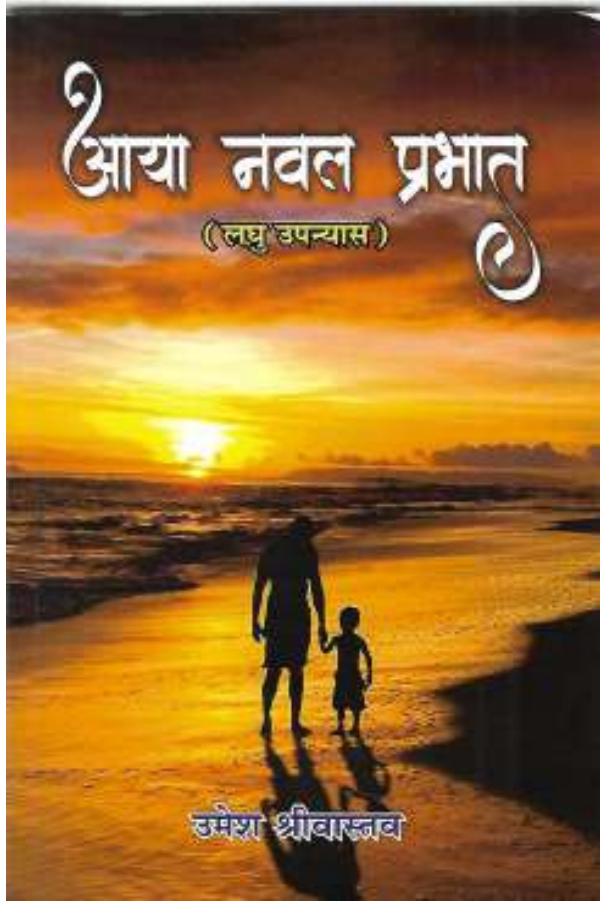
क्रिकेट खेलने वाले देश को गेंद के अधिक विकल्पों की आवश्यकता है और उनकी कंपनी बढ़ते बाजार की जरूरतों को पूरा करने के लिए अपनी उपस्थिति का विस्तार करेगी। कंपनी मेरठ में है, लेकिन उसकी सभी गेंदों को इंग्लैंड में अंतिम रूप दिया जाता है। जाजोदिया ने पिछले हफ्ते बंगलुरु की अपनी यात्रा के दौरान भारत में एक कार्यालय पंजीकृत किया है, जिससे यह स्थिति बदलने वाली है। उन्होंने बीसीसीआई अधिकारियों से भी मुलाकात की जो गेंद का परीक्षण कर रहे हैं। अनुभवी प्रशासक बृजेश पटेल ड्यूक्स के भारत संचालन के प्रमुख होंगे। जाजोदिया ने कहा, मैं मेरठ से गेंदे खरीद रहा था और उन्हें यहां (इंग्लैंड) अंतिम रूप दे रहा था। लेकिन अब हम उन्हें भारत में भी अंतिम रूप देंगे। हम अपनी उपस्थिति बढ़ा रहे हैं क्योंकि हमारा मानना है कि अब भारत में समय सही है। मेरा मतलब है, अर्थव्यवस्था, उत्साह, बीसीसीआई क्रिकेट में जो सुविधाएं दे रहा है, बंगलुरु में जो सुविधा है (वह सब इसके लिए अनुकूल है)।

जब अंगद बड़ा होगा.., लॉर्ड्स के ऑनर्स बोर्ड में शामिल होने पर बोले बुमराह

लंदन। भारतीय टीम के अनुभवी तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह के 5 / 74 के प्रदर्शन को लॉर्ड्स के ऑनर्स बोर्ड में शामिल किया गया है। इस उपलब्धि को वह अपने बेटे अंगद के साथ साझा करना चाहते हैं। दाएं हाथ के गेंदबाज ने दूसरे दिन का खेल समाप्त होने के बाद कहा कि जब उनका बेटा बड़ा होगा तब वह उसे इसके विषय में बताएंगे। 31 वर्षीय गेंदबाज ने इंग्लैंड के खिलाफ जारी तीसरे टेस्ट मैच के दूसरे दिन पहली पारी में पांच विकेट लिए। लॉर्ड्स में बुमराह ने पहली बार टेस्ट मैच की किसी पारी में इतने विकेट लिए हैं। शुक्रवार का खेल समाप्त होने के बाद जब उनसे पूछा गया कि उन्होंने पांच विकेट हॉल हासिल करने के बाद जश्न क्यों नहीं मनाया, इसके जवाब में बुमराह ने कहा– सच तो यह है कि मैं थक गया था। मैं 21 साल के लड़के की तरह उछल–कूद



चर्चित कथाकार और शहर समता अखबार के संपादक श्री उमेश श्रीवास्तव जी का ग्रामीण पृष्ठभूमि पर लिखा बहु प्रतीक्षित



ठिगना भाई ठाढ़े भये (Thigna Bhai Thade Bhaye)

संक्षिप्त समाचार

फ्रांस में एलन मस्क के एक्स की कथित डेटा छेड़छाड़ और धोखाधड़ी की जांच की जा रही

फ्रांसीसी अभियोजकों ने एलन मस्क के सोशल मीडिया मंच एक्स से संबंधित कथित डेटा छेड़छाड़ और धोखाधड़ी की पुलिस जांच शुरू कर दी है। पेरिस अभियोजक कार्यालय ने शुक्रवार को एक बयान में जांच शुरू करने की जानकारी दी। बयान में कहा गया है कि जांच में विशेष रूप से दो कथित अपराधों की जांच की जा रही है। इसने कथित गड़बड़ियों का ब्यौरा नहीं दिया। इसने कहा कि जांच के निशाने पर यह सोशल मीडिया मंच और लोग दोनों हैं। हालांकि इसमें लोगों का नाम नहीं लिया गया और न ही यह बताया गया कि एक्स में कौन सी भूमिका वाले लोग हो सकते हैं।

न्यायाधीश ने ट्रंप प्रशासन को दिया कैलिफोर्निया में आग्रजन संबंधी गिरफ्तारियां रोकने का आदेश

एक संघीय न्यायाधीश ने शुक्रवार को ट्रंप प्रशासन को लॉस एंजिलिस सहित कैलिफोर्निया के सात काउंटी में अंधाधुंध आग्रजन कार्रवाई और गिरफ्तारियों पर तुरंत रोक लगाने का आदेश दिया। प्रवासी अधिकार संगठनों ने पिछले हफ्ते एक मुकदमा दायर किया था, जिसमें उन्होंने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के प्रशासन पर आरोप लगाया कि वह दक्षिणी कैलिफोर्निया में आग्रजन अभियान के दौरान नस्ल के आधार पर लोगों को निशाना बना रहा है। अधिवक्ताओं ने आग्रजन अधिकारियों पर नस्ल के आधार पर लोगों को हिरासत में लेने, बिना वारंट के गिरफ्तारियां करने और लॉस एंजिलिस शहर के एक हिरासत केंद्र में बंदियों को कानूनी सलाह लेने से रोकने का आरोप लगाया है। अमेरिकी आंतरिक सुरक्षा मंत्रालय की सहायक सचिव ट्रिशिया मैकलॉघलिन ने एक ईमेल में कहा, ऐसा कोई भी दावा कि कानून प्रवर्तन एजेंसियों द्वारा किसी व्यक्ति को उसकी नस्ल के कारण निशाना बनाया गया है, घृणित और स्पष्ट रूप से गलत है। न्यायमूर्ति मामी ई. क्रिमपॉन्ग ने एक अलग आदेश जारी कर संघीय सरकार को यह निर्देश दिया कि वह लॉस एंजिलिस स्थित आग्रजन हिरासत केंद्र में वकीलों को बंदियों से मिलने से न रोके। इससे पहले संघीय आग्रजन अधिकारियों ने कैलिफोर्निया में भांग (कैनबिस) के दो खेतों पर छापेमारी करके करीब 200 लोगों को गिरफ्तार किया, जिन पर देश में अवैध रूप से रहने का संदेह है। यह छापेमारी बृहस्पतिवार को की गई थी। घटनास्थल पर मौजूद लोगों ने छापेमारी का विरोध किया, जिसके कारण हालात कुछ देर के लिए तनावपूर्ण हो गए।

दक्षिणी कैलिफोर्निया में लगभग 200 आग्रजक गिरफ्तार : अधिकारी

अमेरिका के संघीय आग्रजन अधिकारियों ने कैलिफोर्निया में भांग (कैनबिस) के दो खेतों पर छापेमारी करके करीब 200 लोगों को गिरफ्तार किया है, जिन पर देश में अवैध रूप से रहने का संदेह है। संघीय आग्रजन अधिकारियों ने यह जानकारी दी। यह छापेमारी बृहस्पतिवार को की गई थी। घटनास्थल पर मौजूद लोगों ने छापेमारी का विरोध किया, जिसके कारण हालात कुछ देर के लिए तनावपूर्ण हो गए। आंतरिक सुरक्षा मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि अधिकारियों ने बृहस्पतिवार को कैलिफोर्निया के कार्पिन्टेरिया और कैमारिलो में आपराधिक तलाशी वारंट पर तामील की और देश में अवैध रूप से रहने के संदेह में कुछ आग्रजकों को गिरफ्तार किया। बयान में कहा गया कि घटनास्थल पर कम से कम 10 बच्चे भी मौजूद थे। मंत्रालय ने कहा कि चार अमेरिकी नागरिकों को अधिकारियों पर हमला करने या उनका विरोध करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। छापेमारी के दौरान कैमारिलो स्थित ‘ग्लास हाउस फार्म्स’ के बाहर लोगों की भीड़ अपने रिश्तेदारों के बारे में जानकारी लेने और आग्रजन प्रवर्तन का विरोध करने के लिए जमा हो गई। कैलिफोर्निया की लाइसेंस प्राप्त भांग उत्पादक कंपनी, ‘ग्लास हाउस’ ने एक बयान में कहा कि आग्रजन एजेंटों के पास वैध वारंट थे। कंपनी ने कहा कि कर्मचारियों को हिरासत में लिया गया है और वह उन्हें कानूनी प्रतिनिधित्व प्रदान करने में मदद कर रही है। इस फार्म में टमाटर और खीरे भी उगाए जाते हैं। बयान में कहा गया है, “ग्लास हाउस ने कभी भी जानबूझकर नियुक्ति प्रथाओं का उल्लंघन नहीं किया है और न ही कभी नाबालिगों को नौकरी पर रखा है।

यूरोपीय संघ के नौसैनिक मिशन ने कहा- हमले में चार लोगों के मारे जाने की आशंका, 11 लापता

दुबई। यूरोपीय संघ के नौसैनिक मिशन ने शुक्रवार को बताया कि यमन के हूती विद्रोहियों के हमले के बाद एक मालवाहक जहाज लाल सागर में डूब गया। इस जहाज पर लाइबेरिया का झंडा था। नौसैनिक मिशन ने कहा कि हमले में कम से कम चार लोगों के मारे जाने और 11 अन्य के लापता होने की आशंका है। यह जानकारी यूरोपीय संघ के श्रॉंपरेशन एस्पाइडसश् नाम के नौसैनिक मिशन ने दी। यह घटना ऐसे समय हुई है जब निजी सुरक्षा बल यूनानी स्वामित्व वाले जहाज एश्टरनिटी सीश् के बचे हुए लोगों की तलाश कर रहे हैं। यह जहाज बुधवार को डूब गया था। यूरोपीय संघ के अभियान के अनुसार, हमले के बाद अब तक 10 लोगों को बचा लिया गया है। इनमें 8 फिलिपिनो चालक दल के सदस्य हैं। बाकी दो जहाज की तीन सदस्यीय सुरक्षा टीम से हैं— इनमें एक यूनानी और एक भारतीय शामिल हैं। मिशन ने बताया कि 15 लोग लापता हैं, जिनमें से चार की मौत होने की आशंका है। यूरोपीय संघ मिशन ने कहा, आस-पास के सभी जहाजों को सतर्क रहने की सलाह दी गई है। हूती विद्रोहियों ने कहा कि कुछ चालक दल के सदस्य उनके कब्जे में हैं। एक दशक से सऊदी अरब से संचालित यमन में अमेरिकी दूतावास ने हूतियों पर नाविकों का श्अपहरणश् करने का आरोप लगाया है। ईरान समर्थित हूतियों द्वारा किया गया यह हमला अब तक के सबसे घातक समुद्री हमलों में से एक है, जो इस महत्वपूर्ण व्यापारिक रास्ते पर किया है। इस रास्ते से पहले हर साल करीब 1 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर का माल जाता था।

आवश्यकता है

उत्तर प्रदेश राज्य के प्रयागराज जिले से प्रकाशित समाचार पत्र को समस्त जनपदों में एवम तहसील व ब्लॉक/शहर में ब्यूरो प्रमुख, चीफ रिपोर्टर, संवाददाता, प्रतिनिधि मण्डल की अवश्यकता है जिन्हे आकर्षण वेतन और भत्ते आदि सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी।

सम्पर्क सूत्र

शहर समता हिन्दी दैनिक /साप्ताहिक समाचार पत्र

मोबाईल नम्बर 9190052 39332

919450482227

ताइवान के सैन्य अभ्यास के जवाब में चीन ने दिरवाए टैंक बोट्स, समुद्री युद्धाभ्यास का वीडियो वायरल

ऑनलाइन एक वायरल वीडियो सामने आया है जिसमें चीन की सेना ‘टैंक बोट्स’ के बड़े को समुद्र में युद्धाभ्यास करते हुए देखा जा सकता है। द सन की रिपोर्ट के अनुसार, पीपुल्स लिबरेशन आर्मी (PLA) ने यह शक्ति प्रदर्शन तब किया जब ताइवान ने अपने इतिहास का सबसे बड़ा सैन्य अभ्यास शुरू किया। एक X (पूर्व में ट्विटर) यूज़र ने लिखा, ताइवान चीनी आक्रमण की कल्पना के आधार पर अभ्यास कर रहा है, जबकि च्। वास्तव में हमला करने की तैयारी कर रहा है। उन्होंने यह भी जोड़ा कि वीडियो में PLA की एक बख्तरबंद उभयचर युनिट को फुजियान प्रांत में समुद्री युद्ध संरचना प्रशिक्षण करते हुए देखा जा सकता है कृ जो



करे तो द्वीप राष्ट्र कैसे प्रतिक्रिया देगा। उन्होंने कहा, हमने हाल के वर्षों में यूक्रेन की स्थिति से सीखा है और हम यह वास्तविक रूप से सोच रहे हैं कि ताइवान को युद्ध की स्थिति में क्या

सामना करना पड़ सकता है। उन्होंने यह भी जोड़ा, कमांडरों को यह सोचना होगा कि उनके सैनिकों को किस प्रकार की चुनौतियां आ सकती हैं, और वे इन जानकारीयों को अपने

क्यूबा के राष्ट्रपति पर अमेरिका का बड़ा एक्शन

वाशिंगटन। अमेरिका ने शुक्रवार को क्यूबा के राष्ट्रपति मिगुएल डियाज़-कैनेल और अन्य शीर्ष नेताओं व कई अधिकारियों पर मानवाधिकार उल्लंघन के आरोप में प्रतिबंध लगा दिए हैं। साथ ही, अमेरिका ने इन नेताओं की वीजा तक पहुंच भी सीमित कर दी है। यह कदम जुलाई 2021 में हुए क्यूबा के बड़े विरोध प्रदर्शनों की वर्षगांठ पर उठाया गया है। बता दें कि जुलाई 2021 में क्यूबा के कई शहरों में बिजली कटौती, भोजन की कमी और आर्थिक संकट को लेकर आम लोगों ने सड़क पर उतरकर विरोध किया था। यह प्रदर्शन किसी विपक्षी पार्टी के नेतृत्व में नहीं, बल्कि स्वतंत्र रूप से शुरू हुए थे। इन प्रदर्शनों को सरकार ने सख्ती से दबा दिया, जिसमें सैकड़ों लोगों की गिरफ्तारी हुई। एक प्रदर्शनकारी की मौत भी हुई थी। मामले में अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रुबियो ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर कहा कि हम उन न्यायिक और जेल अधिकारियों पर भी वीजा प्रतिबंध लगा रहे हैं, जो जुलाई 2021 के प्रदर्शनकारियों की अन्यायपूर्ण हिरासत और यातना में शामिल या सहायक रहे हैं। उन्होंने आगे कहा कि अमेरिका, क्यूबा के लोगों के मानवाधिकार और स्वतंत्रता के लिए खड़ा है।

रूसी तेल खरीद पर अमेरिका का नया प्रतिबंध बिल, भारत पर 500% टैरिफ का खतरा

अमेरिकी सीनेटर और डेमोक्रेटिक पार्टी के सदस्य रिचर्ड ब्लूमेंथल ने रूस पर नए प्रतिबंधों से जुड़े बिल का सार्वजनिक रूप से समर्थन किया है। इस प्रस्तावित कानून में भारत जैसे देशों पर 500: तक का टैरिफ लगाने की सिफारिश की गई है, जो रूस से तेल, प्राकृतिक गैस और पेट्रोलियम उत्पाद खरीदते हैं। ब्लूमेंथल ने रोम से एक वीडियो संदेश में कहा—“मैं अभी यूरोपीय देशों के नेताओं से मिलकर लौटा हूँ। वे यूक्रेन की स्वतंत्रता के समर्थन में प्रेरणादायक प्रतिबद्धता दिखा रहे हैं और अमेरिका के इस रूस प्रतिबंध

यह नया प्रस्ताव चिंता का कारण बन गया है। अन्ता एस्पेन सेंटर की डिप्टी डायरेक्टर प्रेरणा बॉन्ना के अनुसार “यह बिल इसलिए चिंताजनक है क्योंकि अमेरिकी कांग्रेस द्वारा लगाए गए प्रतिबंध मौजूदा व्यापार समझौतों को भी मात दे सकते हैं। अगर यह बिल पास हो जाता है, तो अमेरिकी व्यापार प्रतिनिधियों के पास इसे टालने की शक्ति नहीं रह जाएगी।” उन्होंने आगे कहा कि, “हालांकि सीनेट में इस बिल को 84 सह-प्रायोजक मिल चुके हैं, हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव में इसे अब तक केवल 33 का समर्थन मिला है। भारत के लिए लड़ाई अभी बाकी है। हमारे राजनयिकों को उन प्रतिनिधियों

से संपर्क करना होगा जो फिलहाल वॉशिंगटन में मौजूद नहीं हैं।” अमेरिकी मीडिया रिपोर्टों के अनुसार, यह बिल अमेरिकी राष्ट्रपति (विशेष रूप से ट्रंप यदि फिर से सत्ता में आते हैं) को अधिकार देता है कि वे चुनिंदा देशों के लिए इस बिल के प्रावधानों को छह—छह महीने की दो बार की छूट के साथ निलंबित कर सकें। इस मुद्दे पर भारत सरकार ने भी प्रतिक्रिया दी है। विदेश मंत्री एस. जयशंकर ने बताया कि वॉशिंगटन डीसी स्थित भारतीय दूतावास ने सीनेटर लिंडसे ग्राहम से संपर्क कर भारत की ऊर्जा सुरक्षा को लेकर अपना पक्ष स्पष्ट रूप से रखा है।

तेजी से मंत्रोच्चार हो रहा था, पिता ने बार-बार किया बलात्कार, पड़ोसियों को भी किया शामिल पुलिस प्रमुख की बेटी ने बयां की अपनी दर्दनाक कहानी

न्यू जर्सी के एक लंबे समय से पुलिस प्रमुख रहे व्यक्ति की बेटी ने अपने पिता, एक पड़ोसी और कई अन्य लोगों पर एक दशक से भी ज्यादा समय से यौन और धार्मिक दुर्व्यवहार का आरोप लगाते हुए मुकदमा दायर किया है, जिसमें शैतानी पंथ की गतिविधियों, बाल तस्करी और हिंसा की धमकियों के आरोप शामिल हैं। कोर्टनी टैमग्नी ने आरोप लगाया है कि उनके पिता, लियोनिया पुलिस प्रमुख स्कॉट टैमग्नी, पड़ोसी केविन स्लेविन

और अन्य लोगों ने 4 से 15 साल की उम्र तक उनके साथ दुर्व्यवहार किया। इन आरोपों में बार-बार यौन उत्पीड़न, धमकियाँ और उनके घर और आस-पास के जंगली इलाकों में छैतानी धार्मिक दुर्व्यवहार शामिल है। न्यूयॉर्क पोस्ट की रिपोर्ट के अनुसार, 20 वर्षीय कोर्टनी तामागनी ने एक चौंकाने वाले मुकदमे में अपने पिता लियोनिया पुलिस प्रमुख स्कॉट तामागनी और पड़ोसी केविन स्लेविन का नाम लिया है।

ॐ

सावन के पुनीत अवसर पर

शिव भक्तों को हार्दिक

बधाई एवं शुभकामनाएं

उमा मिश्रा प्रीति

ॐ

सावन के पुनीत अवसर पर

शिव भक्तों को हार्दिक

बधाई एवं शुभकामनाएं

प्रेमा राय प्रयागराज

ॐ

सावन के पुनीत अवसर पर

शिव भक्तों को हार्दिक

बधाई एवं शुभकामनाएं

छाया त्रिवेदी

ॐ

सावन के पुनीत अवसर पर

शिव भक्तों को हार्दिक

बधाई एवं शुभकामनाएं

अनीता दुबे

ॐ

सावन के पुनीत अवसर पर

शिव भक्तों को हार्दिक

बधाई एवं शुभकामनाएं

रचना सक्सेना प्रयागराज

ॐ

सावन के पुनीत अवसर पर

शिव भक्तों को हार्दिक

बधाई एवं शुभकामनाएं

साधना शुक्ला भोपाल

ॐ

सावन के पुनीत अवसर पर

शिव भक्तों को हार्दिक

बधाई एवं शुभकामनाएं

आशा जाकड़

ॐ

सावन के पुनीत अवसर पर

शिव भक्तों को हार्दिक

बधाई एवं शुभकामनाएं

सिद्धेश्वरी सराफ शीलू

ॐ

सावन के पुनीत अवसर पर

शिव भक्तों को हार्दिक

बधाई एवं शुभकामनाएं

सीमा वर्णिका कानपुर